मेरा भारत, मेरा परिवार' कैंपेन मोदी ने किया शुरू

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

लोकशक्ति

RNI Regn. No.7789/1964

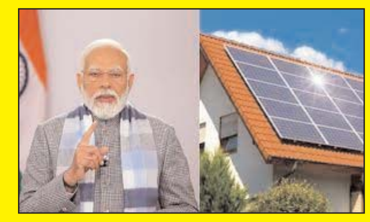
पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के लिए पंजीकरण कराने वाले एक करोड़ से अधिक परिवारों की सराहना

वर्ष-60 › अंक -80 रायपुर रविवार 17 मार्च 2024 शुक्लपक्ष विक्रम संवत 2080 पृष्ठ 8 › मूल्य : 2 रू डाक पंजीयन : C.G./RYP DN/71/2023-25

लोकसभा चुनाव 7 चरणों में

मतदान 19 अप्रैल से शुरू, 1 जून को खत्म; 4 जून को नतीजे

हिस्ट्रीशीटर पर निगरानी रखी जाएगी, ड्रोन से चेकपोस्ट की निगरानी होगी

पैसा बांटने का केस है, फोटो खींचे और चुनाव आयोग को भेज दें: मुख्य चुनाव आयुक्त

एजेंसी।

केंद्रीय चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया. निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता में घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 12 राज्यों में महिला मतदाताओं का अनुपात पुरुष मतदाताओं से अधिक है. चुनाव आयोग ने घोषणा की कि 7 चरणों में होगा लोकसभा चुनाव, 4 जून को आएंगे नतीजे, जिसमें मध्य प्रदेश में चार चरण में वोटिंग होगी. यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सात चरणों में वोटिंग होगी.

यूपी और बिहार में 7 फेज में चुनाव होंगे

किस राज्य में कितने चरण में चुनाव

1 चरण मतदान - अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड **2 चरण में मतदान** - कर्नाटक, राजस्थान, मणिपुर **3 चरण में मतदान** - छत्तीसगढ़, असम **4 चरण में मतदान**- ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड **5 चरण में मतदान** - महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, **7 चरण में मतदान** - उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल **पहला चरण**- 19 अप्रैल 2024 को वोटिंग **दूसरा चरण**- 26 अप्रैल 2024 को वोटिंग **तीसरा चरण**- 7 मई 2024 को वोटिंग **चौथा चरण**- 13 मई 2024 को वोटिंग **पांचवां चरण**- 20 मई 2024 को वोटिंग **छठा चरण**- 25 मई 2024 को वोटिंग **सातवां चरण**- 1 जून 2024 को वोटिंग चार जून को मतगणना।

पूरे देश में पहली बार 85 साल से अधिक उम्र वाले लोग घर बैठे दे सकेंगे वोट

नईदिल्ली,एजेंसी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार पूरे देश में एक व्यवस्था पहली बार लागू होने जा रही है। जो 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाता हैं या जो 40 फीसदी से ज्यादा विकलांगता वाले वोटर हैं, उनके पास फ ॉर्म 12 डी पहुंचाया जाएगा। अगर वे मतदान केंद्र पर नहीं जाना चाहते तो उनके घर जाकर उनका वोट पंजीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मियों को प्रशिक्षित कर दिया है।

बीएलओ घर-घर जाकर फ ार्म 12-डी कराएंगे उपलब्ध

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर संबंधित क्षेत्र के बीएलओ चिह्नित मतदाताओं के घर-घर जाकर फार्म 12-डी भरवाकर जमा करेंगे। इसमें मतदाता की स्वेच्छा है कि वह फ ार्म भरे या न भरे। वह मतदान केंद्र पर भी जाकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदान का प्रयोग कर सकें।

चुनावी नियमों में संशोधन किया था - इससे पहले, सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए चुनावी नियमों में संशोधन किया था। अभी तक 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते थे। यह संशोधन लोकसभा और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा होने से कुछ दिन पहले किया गया था।

चुनाव आयोग ने नौ फरवरी को देश के कुल वोटर्स की संख्या का खुलासा किया था। आयोग ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स से जुड़ी स्पेशल समरी रिवीजन 2024 रिपोर्ट में कहा था कि लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ लोग वोटिंग कर सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है। वहीं 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है।

अनुराधा पौडवाल भाजपा में शामिल

एजेंसी। प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल भाजपा में शामिल हो गई हैं. अनुराधा पौडवाल ने शनिवार 16 मार्च को भाजपा का दामन थाम लिया. भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अनुराधा पौडवाल का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का परिवार और बड़ा हो गया है. देश-विदेश में जब भी भक्ति गीत की बात होती है तो अनुराधा पौडवाल से बड़ा कोई और नाम नहीं है. उन्होंने 35 वर्षों से भक्ति गीत गाया है. अरुण सिंह ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल के क्षेत्र सहित कई अन्य कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास हुआ है, उससे प्रभावित होकर अनुराधा पौडवाल ने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है ।

हेट स्पीच देने वालों की खैर नहीं, 26 सीटों पर भी होंगे उपचुनाव

नईदिल्ली,एजेंसी।

वोटर्स को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, 'पीने का पानी, टॉयलेट्स, रैंप, व्हीलचेयर, हेल्प डेस्क, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर, शेड्स और पर्याप्त रोशनी की सुविधाएं मिलेंगी।'

हिंसा का कोई स्थान नहीं, आपराधिक रिकार्ड वाले उम्मीदवार को करना होगा ये काम: राजीव कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव में हिंसा का कोई स्थान नहीं, इससे बचने के लिए सख्ती से निपटेंगे। हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसी भी उम्मीदवार का आपराधिक रिकार्ड है तो उसे 3 बार अखबार और टीवी पर बताना पड़ेगा। राजनैतिक पार्टी को भी बताना पड़ेगा कि वो उसे टिकट क्यों दे रही है। हमारा वादा इस तरह से राष्ट्रीय चुनाव कराने का है, जिससे विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़े। कंट्रोल रूम में हमेशा एक सीनियर अधिकारी मौजूद रहेगा। शिकायत मिलने पर फौरन सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रहेगी: राजीव कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रहेगी। किसी भी हाल में फेक न्यूज नहीं फैलाने की हिदायत।

जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे: मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, 'जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। हेट स्पीच से बचना होगा। स्टार प्रचारकों को संभलकर बोलना होगा।' **2100 पर्यवेक्षक बनाए गए: राजीव कुमार** - मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इस बार 2100 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं।

26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे: मुख्य चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 26 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे।

कुल कितने महिला और पुरुष वोटर?

पुरुष वोटर- 49.7 करोड़
महिला वोटर- 47.1 करोड़
पहली बार के वोटर- 1.8 करोड़
85 से अधिक उम्र के वोटर्स- 82 लाख
18 से 19 साल की महिला वोटर्स- 85.3 लाख
20 से 29 साल के 19.74 करोड़ वोटर्स हैं।

21.50 करोड़ युवा मतदाता होंगे शामिल

88.4 करोड़ दिव्यांग मतदाता 82 लाख वोटर्स 85 साल से अधिक उम्र के 2 लाख से अधिक वोटर्स की उम्र 100 साल से ज्यादा 48 हजार ट्रांसजेंडर मतदाता भी करेंगे मतदान।

लोकसभा चुनाव में अनुबंधित और अंशकालिक कर्मचारी की नहीं लगेगी ड्यूटी, 100 मिनट में होगा शिकायत का समाधान

राजनीतिक दलों को मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है ताकि बाद में कोई यह नहीं कहे कि हमें नहीं बताया गया. जिलाधिकारियों ने हर जिले में राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की हैं. उनकी आपत्तियों का निराकरण किया गया है. सीईसी ने कहा कि चुनाव कराने को लेकर ECI के सामने 4 चुनौतियां हैं. बाहुबल का इस्तेमाल, धनबल, झूठी खबर और एमसीसी का उल्लंघन.

मुख्य आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोगों को घेरा, शायराना अंदाज में दिया ये जवाब

एजेंसी। राजीव कुमार ने राजनीतिक पार्टियों को हिदायत भी दिया है. उन्होंने गुजारिश करते हुए कहा कि कैंपन के दौरान पर्सनल अटैक से बचे और डेकोरम को मेनटेन रखें. इसके बाद उन्होंने उर्दू अदब के मशहूर शायर बशीर बद्र का ये शेर सुनाया.

दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों ।

राजीव कुमार ने आगे कहा कि आजकल बहुत जल्दी दोस्त और दुश्मन बनने का सिलसिला चल रहा है. इसलिए पार्टियों को इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और आगे कुछ न हो. आपको बता दें कि इससे पहले राजीव कुमार ने रहीम के उस दोहे का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने प्रेम के धागे को बचाए रखने की बात कही थी।

केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन : यासीन मलिक की पार्टी पर 5 साल का बैन

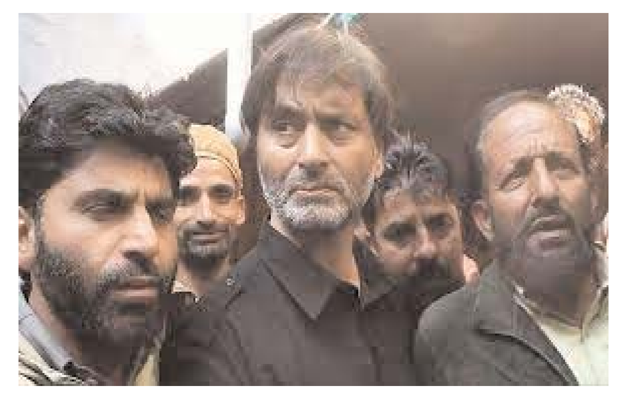

नई दिल्ली. एजेंसी।

कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के संगठन पर प्रतिबंध बढ़ाते हुए, केंद्र सरकार ने शनिवार को घोषणा की कि जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पांच साल की अवधि के लिए एक गैरकानूनी संगठन होगा. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल है.

उन्होंने आगे कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे. गृह मंत्रालय ने 2019 में आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) के तहत मलिक के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था. इस कदम से कुछ दिन पहले, सरकार ने यूएपीए की धारा 3(1) के तहत जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

देश भर में लगी आदर्श आचार संहिता, आज से नहीं होंगे ये काम, यह प्रतिबंध भी प्रभावी

नई दिल्ली. लोकसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इस संहिता के लागू होने से अभिप्राय है कि कुछ काम आज से नहीं होंगे. आचार संहिता के तहत पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए कुछ गाइड लाइन होती हैं. इसके तहत कुछ नियम हैं जिनका राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का पालन करना होता है.

अगर राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है. चुनाव आयोग द्वारा चुनाव तारीखों की घोषणा की तारीख से इसे लागू किया जाता है और यह चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहती है.

लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है. चुनाव के आयोजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती पर संपूर्ण प्रतिबंध होगा. यदि किसी अधिकारी का स्थानांतरण या तैनाती आवश्यक मानी जाती है तो पहले आयोग की अनुमति ली जाएगी. मंत्रियों को अपना आधिकारिक वाहन केवल अपने आधिकारिक निवास से अपने कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए ही मिलेगा. इसमें शर्त है कि इस प्रकार के सफर को किसी चुनाव प्रचार कार्य या राजनीतिक गतिविधि से न जोड़ा जाए. जो योजनाएं और परियोजनाएं चल रहीं हैं उनका इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा. अधिकारियों और कर्मचारियों सहित सरकारी मशीनरी का उपयोग किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के फ ायदे के लिए नहीं होना चाहिए.

'BRS-कांग्रेस ने तेलंगाना के विकास के सपनों को चकनाचूर किया' : मोदी

एजेंसी। तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने कांग्रेस और बीआरएस पर जमकर हमला बोला. पीएम मोदी ने तेलंगाना के नगरकुरनूल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि, पिछले दस सालों में तेलंगाना का विकास मोदी की एनडीए की प्राथमिकता रहा है. लेकिन इन दस वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के दो पाटों में पिसता रहा. एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का. नगरकुरनूल में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि,क कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया. अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है. पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस का बूरी नजर ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुंए से निकले खाई में गिरे. कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए पांच साल भी बहुत हैं.

मच्छर और माफिया दोनो का किया उत्तर प्रदेश से किया खात्मा :मुख्यमंत्री

एजेंसी। रंगो का पर्व होली के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थ नगर वासियों को बड़ा तोहफा दिया है।मुख्य मंत्री ने 1895 करोड़ की लागत से 551 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करते हुए यह परियोजना सिद्धार्थ नगर के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सांसद जगदंबिकापाल की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी जनपदवासी सौभाग्य शाली है कि आपको जगदंबिका पाल जैसा सांसद मिले है जो सिद्धार्थ नगर के विकास के लिए दिन रात एक किए रहते है। आप सबको इतना अच्छा सांसद मिला है इसके लिए आप सब बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि पहले यहां बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, यह जनपद शिक्षा और रोजगार के मामले में पिछड़ा हुआ था, उद्योग धंधे न के बराबर थे, एक तरफ माफिया तो दूसरी तरफ मच्छर से नौजवाओ का बचपन ही खराब हो जाता था। उन्होंने कहा कि हजारो बच्चो को इंसेफ्लाइटिस से बचाने के लिए सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़ी है, तब जाकर इंसेफ्लाइटिस को मात दे पाया हूं।

लोकसभा चुनाव | **चुनावी कार्यक्रम की घोषणा पर बोले मोदी- NDA पूरी तरह तैयार**

हर दिन विकास के नए कीर्तिमान रच रहा भारत

एजेंसी।

पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल पहले जब हमने देश की बागडोर संभाली थी, तब देश और देशवासी इंडी अलायंस के कुशासन से पीड़ित थे. ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं बचा था, जो घोटालों और पॉलिसी पैरालिसिस से अछूता रहा हो. देश निराशा के गर्त में था और दुनिया भी भारत पर भरोसा करना छोड़ चुकी थी. हमने उस परिस्थिति से देश को निकाला और आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है. 140 करोड़ देशवासियों की शक्ति और सामर्थ्य से हमारा देश आज हर दिन विकास के नए कीर्तिमान रच रहा है. आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, और करोड़ों भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं. हमारी सरकार की योजनाएं देश के कोने-कोने और समाज के हर तबके तक पहुंची हैं. हमने शत-प्रतिशत देशवासियों तक पहुँचने के लिए काम किया है और परिणाम हमारे सामने हैं. **हमें देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं** - पीएम मोदी ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में हमें देश के लिए बहुत सारे काम करने हैं. हमारे बीते 10 साल उस गहरी खाई को भरने में भी बीते हैं, जो दशकों तक शासन करने वालों ने बनाई थी. इन 10 वर्षों में देशवासियों में ये आत्मविश्वास आया है कि हमारा भारत भी समृद्ध और आत्मनिर्भर बन सकता है. हमारा अगला कार्यकाल इन संकल्पों की सिद्धि की राह प्रशस्त करेगा. NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और तेज होगी. सामाजिक न्याय के लिए हमारे प्रयास और बढ़ेंगे. हम तेजी से भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे. युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए हमारे प्रयास और मजबूती से आगे बढ़ेंगे. मैं यह साफतौर पर देख रहा हूं कि आने वाले 5 वर्ष हमारे उस सामूहिक संकल्प का कालखंड होगा जिसमें हम भारत की अगले एक हजार वर्ष की विकास यात्रा का रोडमैप तैयार करेंगे. ये समय भारत के सर्वांगीण विकास, समावेशी समृद्धि और वैश्विक नेतृत्व का साक्षी बनेगा।

विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना – प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आज हर भारतीय ये अनुभव कर रहा है कि एक ईमानदार, दृढ़-संकल्पित और मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकार कितना कुछ कर सकती है. इसीलिए, हर देशवासी की हमारी सरकार से अपेक्षाएं भी बढ़ी हुई हैं. इसीलिए, आज भारत के हर कोने से और समाज के हर वर्ग से एक स्वर सुनाई दे रहा है- अबकी बार, 400 पार! आज विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई दिशा. उनका एक ही एजेंडा बचा है- हमें गाली देना और वोट बैंक की राजनीति करना. उनकी परिवारवादी मानसिकता और समाज को बांटने के षड्यंत्र अब जनता ख़ारिज कर रही है. भ्रष्टाचार के अपने ट्रैक-रेकॉर्ड के कारण वो लोगों से आंखे नहीं मिला पा रहे हैं. जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगी.

केजरीवाल को कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मिली

नई दिल्ली दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख रुपए ज़मानत राशि पर बेल दी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए। ईडी ने 31 जनवरी को केजरीवाल को समन जारी किया था और 2 फरवरी को उसके सामने पेश होने को कहा था। यह आप संयोजक को जारी किया गया पांचवां समन था। केजरीवाल के पांचवें समन को नजरअंदाज करने के बाद ईडी कोर्ट गई।

छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव : राजनांदगांव में दूसरे चरण में मतदान

लोकशक्ति।

छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों में इस बार सबकी निगांहे राजगांव लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। भाजपा में सांसद संतोष पांडेय पर एक बार फिर भरोषा जताया है।

कब होंगे राजनांदगांव में चुनाव

आज 16 मार्च शनिवार को निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीट पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रदेश में 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। जिसमें पहले चरण में अतिनक्सल प्रभावित इलाका बस्तर में चुनाव होंगे। बस्तर लोकसभा सीट में 19 अप्रैल को चुनाव होगा। वहीं दूसरे चरण में राजनांदगांव समेत 3 सीट पर चुनाव होगें। जिसमें राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट पर मतदान होंगे। इसके सांथ ही प्रदेश में तीसरे चरण में चुनाव के अनुसार 7 लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी। जिसमें 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चापा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में चुनाव होंगे।

19 अप्रैल शुक्रवार	1 सीट	बस्तर
26 अप्रैल शुक्रवार	3 सीट	कांकेर, राजनांदगांव, महासमुंद
7 मई मंगलवार	7 सीट	रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, दुर्ग और सरगुजा

पांडातराई की जनता का अपार स्नेह और समर्थन के लिए सांसद संतोष ने जताया आभार...

खास खबर...

राजनांदगांव निगम में अधोसंरचना विकास और मूलभूत कार्यों के लिए 8.54 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम में अधोसंरचना विकास के विभिन्न कार्यों और अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कुल आठ करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना विकास के 42 कार्यों के लिए सात करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। शहर में अत्यावश्यक मूलभूत कार्यों के सुचारू संचालन के लिए चुंगी क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत अनटाइड फंड के रुप में विभाग द्वारा एक करोड़ रुपए की भी स्वीकृति दी गई है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा इन राशियों की स्वीकृति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्रीसाव ने सभी कार्यों को अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजनांदगांव में पत्रकारों के लिए आबंटित आवासीय भूखंड में द्वितीय चरण के शेष आवश्यक विकास कार्यों के लिए अधोसंरचना मद के अंतर्गत करीब दो करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इनमें प्रेस क्लब कॉलोनी में 97 लाख 19 हजार रुपए लागत के पी.सी.सी. रोड निर्माण, 34 लाख 64 हजार रुपए लागत के आर.सी.सी. नाली निर्माण और 68 लाख आठ हजार रुपए लागत के बाउंड्रीवॉल निर्माण कार्य शामिल हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राजनांदगांव नगर निगम के लिए अधोसंरचना मद से स्वीकृत कुल सात करोड़ 54 लाख 19 हजार रुपए की राशि से शहर के विभिन्न वार्डों में सी.सी. रोड, पी.सी.सी. रोड, नाला एवं नाली निर्माण, सामुदायिक भवनों के निर्माण, उद्यान निर्माण, शौचालय निर्माण, गेट, दुकान एवं शेड निर्माण, डोम निर्माण, इंटरलॉकिंग, बाउंड्रीवॉल तथा अहाता निर्माण के कार्य कराए जाएंगे।

उपभोक्ता अधिकार दिवस का पर किया गया संगोष्ठी का आयोजन

रायपुर। आज डी.पी. शर्मा अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम रायपुर की गरिमामय उपस्थिति में उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री शर्मा के द्वारा आम उपभोक्ताओं के अधिकार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा उपस्थित समस्त जागरूक उपभोक्ताओं को अपने परिवेश में आने वाले सभी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा किसी भी किस्म की ठगी होने पर उचित मंच में शिकायत करने की प्रक्रिया की जानकारी दिया। साथ ही मुख्य सचिव द्वारा वर्तमान परिवेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले ठगी प्रकरणों के प्रति बचाव के निर्देश का पालन करने की जानकारी दी गई। इस अवसर पर खाद्य नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के निरीक्षक गण, उपभोक्ता प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में विधि छात्रगण उपस्थित रहे।

डब्ल्यूडीसी एवं पीएमकेएसवाई 2.0 योजनांतर्गत संविदा पद भर्ती के दावा आपत्ति की सूचना

रायपुर। डब्ल्यू.डी.सी एवं पी एम.के.एस.वाई. 2.0 योजनांतर्गत जिला रायपुर विकासखंड तिल्दा में संचालित परियोजना में डब्ल्यू.सी.डी.सी हेतु तकनीकी विशेषज्ञ (अभियांत्रिकी), लेखापाल सह डाटा एण्ट्री आपरेटर डब्ल्यू.सी.डी एवं परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी हेतु डब्ल्यू.डी.टी संदस्य (यांत्रिकी), डब्ल्यू.डी.टी संदस्य (समूह विकास) डब्ल्यूडीटी संदस्य (आजीविका), लेखापाल सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर डब्ल्यू.डी.टी के संविदा अनारक्षित पद भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र मंगाया गया था। चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का स्क्रुटनी कर मेरिट सूची तैयार की गई है। मेरिट सूची को दावा आपत्ति हेतु रायपुर जिले के ऑफिसियल वेबसाईड तंपचनतण्हवअण्पद में 15 मार्च को अपलोड कराया गया है।

बीते दिन के फैसलें होंगे लाभकारी

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लिये पांच अहम फैसले

सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा चार फीसदी, पेंशनरों को भी होगा लाभ

- सातवें वेतनमान के एरियर्स के अंतिम किश्त की राशि भी मिलेगी
- कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गठित की गई समिति
- पंचायत सचिवों को 55 दिनों की हड़ताल का होगा वेतन भुगतान, अर्जित अवकाश में समायोजित होगी हड़ताल अवधि
- पत्रकारों के खिलाफकिये गये कथित झूठे मुकदमों एवं उत्पीड़न के मामलों में न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

लोकशक्ति।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारी-कर्मचारियों तथा मीडियाबंधुओं के हित में पांच अहम फैसले लिये। इनमें अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर चार प्रतिशत का महंगाई भत्ता देना भी शामिल है। इसका लाभ पेंशनरों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते की यह राशि एक मार्च 2024 की तिथि से मिलेगी। राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारिक की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई है जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी और इनके निराकरण से संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। अर्जित अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्यौहार में कर्मचारियों के परिवारों में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे।

अब महंगाई भत्ता हुआ 46 प्रतिशत

महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में 04 प्रतिशत महंगाई भत्ते में एवं पेंशनरों के महंगाई राहत में 04 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। यह महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। इसके फ्लस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर सातवें वेतनमान में 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में यह 230 प्रतिशत हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3 लाख 90 हजार कर्मचारी तथा 1 लाख 20 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा।

सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त भी मिलेगी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों-कर्मचारियों की सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त प्रदान करने की घोषणा भी की।

हड़ताल अवधि का वेतन पंचायत सचिवों को मिलेगा

मुख्यमंत्री ने आज संवेदनशील निर्णय लेते हुए ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत दी। ग्राम पंचायत सचिव पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन हड़ताल पर थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिनों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय-भार आएगा।

कर्मचारियों की समस्याओं पर बनी समिति

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी भाईयों ने बहुत सी मांगों और समस्याओं के संबंध में अपनी बातें हमसे साझा की हैं। हम उनकी समस्याओं का पूरी संवेदनशीलता से समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के हल के लिए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई है। समिति विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर शासन को कर्मचारी हित में उचित सुझाव देगी। अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त सदस्य होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा) सदस्य सचिव होंगे।

पत्रकारों को न्याय दिलाने गृह सचिव की अध्यक्षता में बनेगी कमेटी

मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों एवं मीडियाजगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आईं थीं। इस संबंध में हम गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि इस कमेटी में पत्रकारों समेत अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाएगा।

कलेक्टर ने विद्यार्थियों से लिया फीड बैक

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह आज मोतीबाग परिसर स्थित तक्षशिला पुस्तकालय का निरीक्षण करने पहुँचे। उन्होंने लाइब्रेरी में अध्ययनरत युवाओं से लाइब्रेरी में जुड़े सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं पर चर्चा किया।

कलेक्टर ने सभी युवाओं को बारी बारी सुना एवं उनके सुझाओं पर अमल करने की बात कही। सभी युवाओं ने एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह का तक्षशिला लाइब्रेरी प्रारंभ करने पर उनका धन्यवाद किया। कलेक्टर ने कहा कि यहाँ पर रीडिंग ज़ोन के साथ ही पुस्तकालय का भी सुविधा है। आप सभी के भविष्य एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की किताब उपलब्ध कराई गई। अभी भी यदि कोई किताब अगर उपलब्ध नहीं है तो आप अपना सुझाव पूर्ण विवरण के साथ दीजिए हम उस पर यथासंभव आवश्यक कार्यवाही करेंगे। निरीक्षण के दौरान अध्ययनरत युवाओं ने कलेक्टर से कुछ किताबों की माँग की थी जिसको रोजगार अधिकारी एवम नोडल अधिकारी श्री केदार पटेल द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर कुछ समय के अंतराल पर ही लॉ सहित अन्य किताबों को उपलब्ध करा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस लाइब्रेरी की कुछ सुविधा नई है और जब कोई नई सुविधा प्रारंभ होती है तब उसको मूर्त रूप में आने के लिए समय लगता है। शासन-प्रशासन की कोशिश और आप सभी युवाओं के सुझाव से तक्षशिला लाइब्रेरी को हमेशा बेहतर से भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। डॉ सिंह ने कहा कि परिसर में साफ-सफाई रखी जाए और गर्मी को देखते हुए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही परिसर में संचालित कैंटिन में उपयुक्त दरों पर नाश्ता और बैठने की व्यवस्था भी की जाए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, रोजगार अधिकारी एवं लाइब्रेरी के नोडल अधिकारी केदार पटेल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सड़कों पर महीनों भटक रहे रुपेश देवांगन भी अब अपने पैरों से अपने घर जा सकेगा

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जन चौपाल के दौरान रुपेश देवांगन को उनका आधार कार्ड सौपा। श्री देवांगन जो एक वर्ष पूर्व रायपुर के सड़कों पर बदहवांस हालात में भटक रहे थे, जिनको रायपुर के अपना घर आश्रम के वालंटियर्स द्वारा आश्रम लाया गया जहा उनका बेहतर सेवा और देख भाल किया जा रहा है। देवांगन जिनका दोनो पैर नहीं है, उनको कृत्रिम पैर लगवाने की पहल चल रही है जिसके लिये श्री देवांगन का आधार कार्ड की आवश्यकता थी। देवांगन के आधार कार्ड के बारे में जानकारी लेने कलेक्टर जन चौपाल ले जाया गया, जहां कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह से मिलकर रुपेश देवांगन के बारे में जानकारी देते हुए मदद के लिए निवेदन किया गया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश से श्री रुपेश का आज आधार निकलवाया गया एवं कलेक्टर के द्वारा श्री रुपेश को आधार कार्ड सौंपा गया। अब रूपेश देवांगन का आधार प्राप्त होने से उनका मूल निवास के बारे में जानकारी प्राप्त हो सका है। अपना घर आश्रम और ज़िला प्रशासन रुपेश देवांगन के परिवार से संपर्क साधने का प्रयास कर रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार के तीन माह पूरे

सरकार ने लिए जनहित में बड़े फैसले, लोगों ने जताया आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से यहां उनके निवास कार्यालय में विधायक रोहित साहू के नेतृत्व में राजिम विधानसभा के क्षेत्रवासियों ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तीन माह की अल्प अवधि में जनहित में लिए गए बड़े फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया।

लोगों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कम समय में ही सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जिसका लाभ पूरे प्रदेश के लोगों को मिल रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय से कहा कि नई सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में राज्य में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों को स्वीकृति देकर विकास का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य के 12 लाख से अधिक किसानों को धान का 2 वर्ष का बकाया बोनस 3716 करोड रुपए भी तत्काल प्रदान किया गया। साथ ही प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा भी अमल में लाई गई। राज्य में इस वर्ष 145 लाख टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से भुगतान भी किया गया है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 24 लाख 72 हजार किसानों के खाते में 13,320 करोड रुपए की राशि अंतरित की गई है।

प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार के तीन माह के कार्यों पर हर्ष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य की माता बहनों के लिए सरकार ने महतारी वंदन योजना लागू कर दी है। जिसके तहत 70 लाख से अधिक माताओं के खाते में ?1000 के मान से 655 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है।

पीएससी की पिछली परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है।अयोध्या में भगवान श्रीराम का दर्शन करने के लिए श्रीरामलला दर्शन योजना शुरू हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास के लिए नियद नेल्लानार यानी आपका अच्छा गांव योजना प्रारंभ हुई है। इस तरह छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास के पथ पर बहुत तेजी से अग्रसर है। इस अवसर पर सर्वश्री प्यारेलाल सोनकर, राजेश साहू मनीष हरित, राजू साहू, मोती निषाद, रामाधार साहू, केजउ निषाद, अंकुर पहाड़िया, ईश्वर साहू तथा भागीरथी सिन्हा आदि उपस्थित थे

खास - खबर

प्लेट मिल ने दैनिक उत्पादन का बनाया नया कीर्तिमान

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र की प्लेट मिल, जिसका हाल ही में 45 दिनों का वृहद कैपिटल रिपेयर पूरा हुआ, ने 14 मार्च 2024 को 901 स्लैब से 6,680 टन प्लेटों की रोलिंग कर दैनिक उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है। मिल ने 21 अक्टूबर 2023 को हासिल किए गए 6,532 टन के पिछले दैनिक रिकॉर्ड को पार कर लिया है। कैपिटल रिपेयर के दौरान, रफिंग स्टैंड और फिनिशिंग स्टैंड की मशीनिंग के द्वारा त्रुटियों को सुधारा गया। इस रिपेयर के बाद, मिल ने 8 मिलीमीटर मोटाई की प्लेटों की रोलिंग का काम शुरू किया जिनका उत्पादन पिछले तीन वर्षों से बंद था। 11 मार्च 2024 को मिल ने 8 मिमी मोटाई के 110 टन प्लेटों की रोलिंग की। भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी अनिर्बान दासगुप्ता ने टीम प्लेट मिल, स्टील मेल्टिंग शॉप-2 और संबंधित शॉप्स को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी तथा उन्हें आगे भी श्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह किया। कार्यपालक निदेशक (वर्क्स) अंजनी कुमार ने सुरक्षा, गुणवत्ता व समयबद्धता को प्राथमिकता देते हुए रिकॉर्ड उत्पादन हेतु प्लेट मिल नेतृत्व की प्रशंसा की तथा सभी संबंधित विभागों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उत्पादन लक्ष्य हासिल करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्लेट मिल बिरादरी को उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बधाई दी है। उन्होंने स्टील मेल्टिंग शॉप-2 को कास्ट स्लैब की निरन्तर आपूर्ति, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल विभाग तथा रिसर्च एंड कंट्रोल लेबोरेटरी सहित संबंधित शॉप्स को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया, जिसके बिना यह रिकॉर्ड उत्पादन संभव नहीं था।

आम, फलबहार की नीलामी एक अप्रैल को

दुर्ग। जिले की शासकीय उद्यान रोपणी रूआबांधा के आम, फलबहार (चौसठ पौधे) की नीलामी एक अप्रैल 2024 को शासकीय उद्यान रोपणी रूआबांधा में किया जाएगा। इच्छुक व्यापारी विस्तृत जानकारी के लिए रूआबांधा रोपणी के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

मृतक के परिजनों को मिली 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता

दुर्ग। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने दुर्घटना में मृतक के परिजनों को 12 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पथरिया थाना बोरी जिला दुर्ग निवासी श्रीमती नागेश्वरी निषाद की विगत 10 जुलाई 2023 को आग स जल जाने से मृत्यु हो गयी थी। इसी प्रकार ग्राम कोपेडीह, तहसील पाटन जिला दुर्ग निवासी ओमप्रकाश देवांगन की विगत 24 मई 2022 को नदी के पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. श्रीमती नागेश्वरी निषाद के पति मनोज केंवट को, स्व. ओमप्रकाश देवांगन की माता श्रीमती नंदनी देवांगन को, स्व. दानेश्वर गोस्वामी के पिता द्वारिकापुरी गोस्वामी को एवं स्व. आयान हुसैन के पिता मोहम्मद शकील को 4-4 लाख रूपये अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

मां रेणुका यलम्मा जात्रा में झूमे श्रद्धालु, समाज के लिए विधायक रिकेश ने की बड़ी घोषणा

मां मंकिनम्मा मंदिर परिसर के चारों ओर होगी फेंसिग, सामुदायिक भवन के लिए मिलेंगे विधायक निधि से पांच लाख रुपए

भिलाई। श्रीश्रीश्री मां मंकिनम्मा सेवा समिति द्वारा मां रणुका यलम्मा जात्रा समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर समाज के श्रद्धालुओं ने भव्य शोभायात्रा (जात्रा) निकाली गई। यह शोभायात्रा आंध्रा स्कूल ग्राउंड कैंप-1 से निकाली गई जो मां मंकिनम्मा मंदिर, जवाहर नगर तक पहुंची। मंकिनम्मा मंदिर परिसर में भव्य समारोह का आयोजन किया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन उपस्थित रहे।

मां रणुका यलम्मा जात्रा समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे हुई। जात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियों का समावेश किया गया। माता के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं पदयात्रा करते हुए मां मंकिनम्मा मंदिर परिसर पहुंचे। मंदिर परिसर में सम्मान समारोह व विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि विधायक रिकेश सेन ने समाज के लोगों का अभिनंदन किया और मां मंकिनम्मा के दर्शन कर उनकी विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया और बच्चों के साथ थोड़ी हंसी ठिठोली की।

विधायक रिकेश ने की पांच लाख रुपए देने की घोषणा

कार्यक्रम के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने विधायक रिकेश सेन का महा पुष्पहार से स्वागत व सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक रिकेश सेन ने समाज के लोगों के लिए बड़ी घोषणा की। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि मां मंकिनम्मा का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। आप सभी के सहयोग व मां के आशीर्वाद से आज आपकी सेवा में हूं। उन्होंने कहा कि समाज के लोगों ने मंदिर के चारो ओर फेंसिंग कराने की मांग की है। मंच से विधायक रिकेश सेन ने मंदिर के चारों ओर फेंसिंग कराने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने यहां एक सामूदायिक भवन निर्माण के लिए विधायक निधि से पांच लाख रुपए देने की घोषणा भी की। विधायक रिकेश की घोषणा का सभी समाज के लोगों ने आभार जताया। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में श्रीश्रीश्री मां मंकिनम्मा सेवा समिति के संयोजक संयोजक एम. जगपति राव, समाज सेवी निरज सिंह, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण चौधरी, अध्यक्ष यू. गणपति राव, महासचिव एल काली दास व कोषाध्यक्ष एम अनंत राव का विशेष योगदान रहा।

खुर्सीपार क्षेत्र के सीवर लाईन, चेम्बर निर्माण कार्य का रास्ता खुला

भिलाई निगम के महापौर परिषद ने दी स्वीकृति

भिलाई। खुर्सीपार के बरसो पुराने सीवरेज लाईन एवं चेम्बर निर्माण कार्य की स्वीकृति सहित भिलाई के विभिन्न खेल मैदानों के संधारण, संचालन एवं रखखाव के लिए रूचि की अभिव्यक्ति बुलाये जाने तथा स्वच्छता श्रृंगार योजनांतर्गत सामुदायिक शौचालय के रख रखाव एवं संचालन कार्य के अवधि में वृद्धि किये जाने के प्रस्ताव को भिलाई निगम के महापौर परिषद ने दी स्वीकृति।

महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में संपन्न हुई। बैठक में जोन-4 शिवाजी नगर खुर्सीपार में सीवर लाईन एवं चेम्बर निर्माण कार्य लागत राशि 7 करोड 29 लाख 90 हजार कुल तीन भाग मे कार्य कराये जाने हेतु

सदस्यो ने विस्तृत चर्चा कर सीवरेज जैसे जनहितकारी अतिआवश्यक कार्य को ध्यान में रखते हुए कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी प्रकार केम्प-2 तालाब सौंदर्यीकरण अंतर्गत रिटेनिंग वॉल, उद्यान विकास, विद्युत व्यवस्था के साथ तालाब का सिल्ट , मलबा सफाई एवं परिवहन जन सहभागिता से कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार पश्चात निविदा के माध्यम से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक में पुन: प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

निगम के सभी जोन क्षेत्र में संचालित सामुदायिक शौचालय के रखरखाव एवं संचालन शासन के स्वच्छता श्रृंगार योजना के तहत वर्तमान एन.जी.ओ. एवं स्व सहायता समूह के कार्यो के गुण-दोष के आधार पर समय वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में हाउसिंग बोर्ड काली बाड़ी चौक से भगवा चौक के सड़क चौड़ीकरण कार्य हेतु ट्रांसफार्मर एवं विद्युत पोल को हटाये जाने, जोन-2 के अंतर्गत शांति नगर दशहरा मैदान, जवाहर नगर स्पोर्टस काम्पलेक्स,हाउसिंग बोर्ड क्रिकेट मैदान तथा जोन-3 के सेक्टर 2 फूटबाल मैदान का संचालन, संधारण एवं रखरखाव हेतु संस्था से रूचि की झअभिव्यक्ति मंगवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। महापौर परिषद के सदस्य सीजू एन्थोनी, लक्ष्मीपति राजू, केशव चौबे, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, साकेत चंद्राकर, आदित्य सिंह, चन्द्रशेखर गंवई, मन्नान गफ्फार खान, एकांश बंछोर, रीता सिंह गेरा, नेहा साहू सहित विभागीय सचिव एवं अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

जिले के 6 खिलाड़ियों को शहीद राजीव पाण्डेय खेल पुरुस्कार से नवाजा गया

भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण 2024 मे छत्तीसगढ़ नेटबॉल के दुर्ग जिले के 6 खिलाड़ियों को वर्ष 2020-2021 के लिए शहीद राजीव पाण्डेय खेल पुरुस्कार से नवाज़ा गया, यह सभी खिलाडी जिला दुर्ग के भिलाई नगर के निवासी है।

इन खिलाड़ियों ने वर्ष 2019-2020 मे आयोजित 37वी सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता (पुरुष) मे छत्तीसगढ़ के लिए कस्य पदक प्राप्त किया,वही वर्ष 2020-2021 मे 38वी सीनियर राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता (पुरुष) मे अपने खेल के आधार पे छत्तीसगढ़ का लोहा मनवाते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया।

इनकी उपलब्धियों के लिए छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा कलयाण विभाग द्वारा शहीद राजीव पाण्डेय पुरुस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के नाम.(1). प्रशांत जेकब (2).नीलेश शर्मा (3). प्रकाश विश्वकर्मा (4). इमरान खान (5). मनोज साहू (6). मोहन राव है।

135 करोड़ 34 लाख 90 हजार का बजट पारित, जनता के हित और विकास में टेक्नोलॉजी का उपयोग - महापौर

रिसाली। रिसाली महापौर शशि सिन्हा ने शुक्रवार को 135 करोड़ 34 लाख 90 हजार का 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत की। वे ठीक 10:15 बजे सदन पहुंची। महापौर द्वारा लगभग 15 मिनट के बजट अभिभाषण प्रस्तुत करने के बाद सभापति केशव बंछोर ने विशेष सभा में बजट संकल्प पारित कराया। महापौर ने 6.91 लाख लाभ का बजट बताया। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने सदन में पहले हाथ उठाया फिर बजट के समर्थन में मेज थप थपाकर ध्वनी मत से पारित किया।

महापौर शशि सिन्हा ने अपने बजट अभिभाषण में कहा कि गत वर्षों में रिसाली शहर में अपनी उदयगामी पहचान बनाई है और हम रिसाली को उच्चस्तरीय शहरों के रूप में पहचान दिलाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जनता के हित और विकास में टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। इसके लिए रिसाली निगम और स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्व विद्यालय के बीच एक अनुबंध किया जा रहा है। इस अनुबंध के तहत रिसाली निगम क्षेत्र की जनता के लिए सुविधा डेवलप करेंगे। उन्होंने बताया कि इस विषय को लेकर स्वयं और सभापति केशव बंछोर कुलपति एम.के.वर्मा से चर्चा भी कर चुके है। बजट के लिए बुलाए गए विशेष सभा में महापौर परिषद के सद्स्य चन्द्रभान सिंह ठाकुर, गोविन्द चतुर्वेदी, सनीर साहू, परमेश्वर कुमार, सोनिया देवांगन नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू आदि उपस्थित थे।

बजट अभिभाषण के बाद सभापति केशव बंछोर ने पार्षदों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू समेत पार्षद धर्मेन्द्र भगत, विधि यादव, हरीशचंद्र, खिलेन्द्र चन्द्राकर व सविता ढवस, रमा साहू ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया। बाद में सभापति ने बहुमत के आधार पर बजट संकल्प पारित किए जाने की घोषणा की।

एक नजर आय व्यय पर

अनुमानित बजट - 13534.90
राजस्व आय - 5225.06
पूंजीगत प्राप्तिया - 8309.84
राजस्व व्यय - 5221.80
पूंजीगत व्यय - 8306.30

मुक्तिधामों के कायाकल्प के लिए विधायक गजेंद्र यादव एवं महापौर धीरज बाकलीवाल ने किया भूमिपूजन

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत शहर के मुक्तिधामों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मुक्तिधाम परिसर में शेड निर्माण,बाउंड्रीवाल,सहित विभिन्न अन्य कार्य एवं पेयजल तथा बैठक व्यवस्था दुरुस्त किया जायेगा। शोक सांत्वना देने हॉल बनाया जाएगा।

एक साथ दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र के 8 मुक्तिधाम परिसर पर होने वाले कार्य के लिए आज विधायक गजेंद्र यादव,महापौर धीरज बाकलीवाल एवं रजनी विजय बघेल, के मुख्य अतिथि में भूमिपूजन किया गया।कार्यक्रम के दौरान सभापति राजेश यादव,आयुक्त लोकेश चन्द्राकर,लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी,संजय कोहले,नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा,

साहू,उपनेता प्रतिपक्ष देवनारायण चन्द्राकर,भोला महोविया,शिवेंद्र परिहार,अरुण सिंह,नरेंद्र बंजारे,जमुना,पार्षदगण उपास्थिति

थे।विधायक गजेंद्र यादव के प्रयासों से शहर के मुख्य 8 स्थानों में मुक्तिधामों के कायाकल्प के लिए शासन से 2.48 करोड़ की स्वीकृति कराई,स्वीकृति मिलने के बाद किये गए भूमिपूजन के तहत वार्ड 15 करहीडीह, वार्ड 17 कादम्बरी नगर, वार्ड विद्युत सब स्टेशन के सामने, वार्ड 56 बघेरा, वार्ड 57 उरला, वार्ड 60 रायपुर नाका, वार्ड 11 हरनाबाँधा एवं वार्ड 50 बोरसीभाठा के मुक्तिधाम शामिल है।इन मुक्तिधामों में बाउंड्रीवॉल,बारिश के सीजन में कीचड़ से बचने पेवर ब्लॉक, शवदाह गृह शेड रिपेयरिंग, शवदाह गृह के नए शेड निर्माण,शोक सभा के लिए सभागृह,शौचालय, बैठने के लिए चबूतरा, पेयजल व्यवस्था, सहित अन्य निर्माण कार्य होंगे। वार्ड 11 में मुक्तिधाम जीर्णोद्धार कार्य करने भुमिपूजन किया गया। विधायक गजेंद्र यादव उक्त कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ कर गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।उन्होंने कहा कि इसी प्रकार विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर शहर में कराए जाएंगे।इस अवसर पर विधायक गजेंद्र यादव व महापौर धीरज बाकलीवाल का पार्षद एवं स्थानीय लोगो ने आभार व्यक्त किया।

नरेश तेजवानी,कविता तांडी,काशीराम कोसरे, खिलावन मटियारा,सतीश देवांगन, अमित देवांगन,बिजेंद्र भारद्वाज,बृजलाल पटेल,अजित वैध,चमेली साहू,कुमारी साहू,कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम, सहायक अभियंता आर.के. पलिया, सहायक अभियंता गिरीश दीवान, सजय ठाकुर,कुलेश्वर साहू, गुड्डू यादव व निगम अधिकारी व स्थानीय क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, युवा एवं महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

डीजल पेट्रोल में मात्र 2-2 रुपये की कमी चुनावी तुष्टीकरण : कुरैशी

भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मंत्री बदरूदीन कुरैशी ने केन्द्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के 4 दिन पूर्व देश की जनता को तुष्टीकरण करने के उदेश्य से केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इशारे पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2-2 रूपये कम किया है।

जिस प्रकार पिछले सप्ताह से पूरे देश के राज्यों में घूम घूम कर आमजनता को तुष्टीकरण करने के उदेश्य से नरेन्द्र मोदी हर राज्यों में जाकर हजारों करोड़ो लाखों रूपये की योजनाओं की मात्र घोषणा और शिलान्यास करते जा रहे है जबकि देश में पिछले कई महिनों से डीजल और पेट्रोल का रेट बढते चला जा रहा है जबकि डीजल पेट्रोल की बढती महंगाई को देखकर केन्द्र सरकार के राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी पार्टी के राज्य सरकारों को एक्साइज डयूटी वेट कम करने के लिए निर्देश दिये केन्द्र उसके बावजूद मध्यप्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र इस प्रकार कई राज्यों में एक्साइज डयूटी और वेट कर कम नहीं किया गया आज चुनावी घोषणा होने के 3-4 दिन पूर्व देश की जनता को गुमराह करने के उदेश्य से बढते डीजल और पेट्रोल की कीमतों को मात्र 2-2 रूपये कम करके आमजनता का तुष्टीकरण किया जा रहा है।

मनमोहन सिंह जी की सरकार 2014 में केन्द्र में सरकार थी क्रुड आइल 108 डॉलर प्रति बैरल था ऐसी स्थिति में भी पेट्रोल की कीमत 71 रूपये 51 पैसा प्रति लीटर और डीजल 57 रूपये 28 पैसा प्रति लीटर था जबकि फरवरी 2021 में मोदी सरकार में क्रुड आईल की किमत 61 डॉलर प्रति बैरल है।

उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89.29 रूपये प्रति लीटर डीजल की किमत 79.70 रूपये प्रति लिटर था मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज डयूटी कुल 12 बार बढ़ाया है लेकिन घटाया सिर्फ 2 बार है पहली बार केन्द्र सरकार ने अक्टूबर 2017 में एक्साइज डयूटी 2 रूपये घटाई थी दूसरी बार अक्टूबर 2018 में एक्साईज डयूटी 2 रूपये घटाई थी इसके अलावा केन्द्र सरकार ने हर बार एक्साइज डयूटी बढाई मई 2020 में एकसाथ पेट्रोल पर 10 रूपये और डीजल पर 13 रूपये एक्साइज डयूटी बढाई थी जिससे केन्द्र को जाने वाला पेट्रोल का एक्साइज डयूटी 32.98 और डीजल 31.83 पैसा हो गया यह सच्चाई है कि एक्साइज डयूटी मोदी सरकार द्वारा लगाई गई है आज तक पिछला रिकार्ड देख लिया जाये उतनी कभी किसी कार्यकाल में एक्साइज डयूटी नहीं लगी यूपीए सरकार में डीजल पर वेट 3.56 पैसा था जबकि अब करीब 32 रूपया है जबकि क्रुड आइल डालर कम होने के बावजूद केन्द्र की सरकार एक्साइज डयूटी वेट कर कभी कम नहीं करी आज भी केन्द्र सरकार देश की महंगाई शिक्षित बेरोजगारों की बेरोजगारी के प्रति कोई चिंता नहीं है।

संपादकीय

कीचड़ उछालना केजरीवाल की बौखलाहट

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लागू होने का बेहूदा, बेतुका एवं उच्छृंखल विरोध कर रहे हैं। वे एवं अन्य विपक्षी दलों के नेता सीएए रूपी उजालों पर कालिख पोतने का प्रयास करते हुए आकाश में पैबन्द लगाना चाहते हैं और सछिद्र नाव में सवार होकर राजनीति-सागर की यात्रा करना चाहते हैं। ऐसा करते हुए वे न केवल आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि अराजकता का माहौल निर्मित कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में लाखों की संख्या में पाकिस्तान, बांगलादेश और अफ्गानिस्तान से हिंदू व सिख आने से चोरी, रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ने की बात कहकर केजरीवाल ने इन लोगों की भावनाओं को आहत किया हैं। केजरीवाल के बयान भ्रामक, बेबुनियाद एवं विध्वंसात्मक इसलिये है कि सीएए नये आने वाले हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध एवं पारसी लोगों पर लागू ही नहीं होगा, बल्कि देश में वर्ष 2014 एवं उससे पहले आये ऐसे शरणार्थियों को सीएए के अन्तर्गत नागरिकता देने का कानून हैं। अब इससे नये लोगों के आने, बेरोजगारी बढ़ने एवं कानून-व्यवस्था चरमरा के प्रश्न कहां से आ गये? विपक्षी दल इस कानून के सन्दर्भ में कपट और झूठ का सहारा लेकर जिस तरह दुष्प्रचार में जुट गए हैं, वह केवल अप्रत्याशित ही नहीं, खतरनाक भी है। वोट बैंक की बेहद सस्ती, घटिया और गंदी राजनीति के चलते किया जा रहा यह खतरनाक एवं देश तोड़क दुष्प्रचार न केवल लोगों को बरगलाने, बल्कि उकसाने वाला भी है।

क्या सैनी से भाजपा के हित साधेगें?

अजीत द्विवेदी

नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने को भाजपा का नायाब दांव माना जा रहा है। माना जा रहा है कि एक दांव से भाजपा ने कई लक्ष्य साध लिए हैं। अब भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इन्कम्बैंसी खत्म हो जाएगी। किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी। पिछड़ी जातियों का पूरी तरह से ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हो जाएगा और दूसरी ओर त्रिकोणात्मक लड़ाई में दुष्यंत चौटाला जाट वोटों का बंटवारा करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो जाएगा? क्या राजनीति सचमुच इस तरह एकरेखीय और इतनी ही सरल होती है कि चुनाव से पहले एक चेहरा बदल देने से पूरी राजनीति बदल जाएगी? कुछ राज्यों जैसे गुजरात और उत्तराखंड में ऐसा जरूर हुई है लेकिन उन राज्यों की राजनीति और सामाजिक संरचना दोनों भिन्न थे। हरियाणा की राजनीति उनसे अलग है। उसी तरह जैसे कर्नाटक की राजनीति अलग थी और वहां चेहरा बदलने का दांव नहीं चला। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि हरियाणा में यह नायाब दांव अनिवार्य रूप से विफल ही हो जाएगा।बहरहाल, मनोहर लाल खट्टर लगातार नौ साल से अधिक समय से मुख्यमंत्री थे तो क्या चुनाव से पहले उनको बदल देने से उनकी सरकार के खिलाफ अगर कोई एंटी इन्कम्बैंसी थी तो वह खत्म हो जाएगी? ध्यान रहे पिछले 10 साल में जितने राज्यों में भाजपा की सरकार बनी और जो भी मुख्यमंत्री बना उनमें से किसी का कार्यकाल इतना लंबा नहीं रहा, जितना खट्टर का था। सो, उनके खिलाफबाकी राज्यों से ज्यादा एंटी इन्कम्बैंसी स्वाभाविक रूप से बनी होगी। दूसरे, उनके कार्यकाल में दोनों किसान आंदोलन हुए, जिनके केंद्र में हरियाणा रहा।पहले आंदोलन के समय किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए खट्टर सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसने किसानों को बुरी तरह से नाराज किया था। दूसरे आंदोलन में भी पंजाब और हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए या नकली गोलियों से फायरिंग हुई उससे किसान नाराज हैं। उनकी नाराजगी निश्चित रूप से सिर्फमनोहर लाल से नहीं होगी।भाजपा पिछले करीब 10 साल से हरियाणा में जाट बनाम गैर जाट की राजनीति करती रही है। उसने 10 साल पहले हरियाणा सहित कई राज्यों में शक्तिशाली और सत्ता की स्वाभाविक दावेदार मानी जाने वाली जातियों को छोड़ कर दूसरी जातियों को सत्ता सौंपी। महाराष्ट्र में गैर मराठा देवेंद्र फड़नवीस, हरियाणा में गैर जाट मनोहर लाल खट्टर और झारखंड में गैर आदिवासी रघुबर दास मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मोटे तौर पर यह राजनीति कामयाब रही है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनी फिर भी भाजपा अपना वोट बढ़ाने और उसे बनाए रखने में कामयाब रही।इसी राजनीति के तहत पंजाबी समुदाय के मनोहर लाल को हटा कर पिछड़ी जाति के नायब सिंह सैनी सीएम बनाए गए हैं। गैर जाट चेहरा बता कर उनको नायाब दांव की तरह पेश किया जा रहा है। यह सही है कि राज्य में एक तिहाई से ज्यादा आबादी पिछड़ी जातियों की है लेकिन क्या सैनी के नाम से सब भाजपा से जुड़ जाएंगे? दूसरा सवाल यह है कि गैर पिछड़ी जातियों का क्या होगा? क्या वे भी सैनी को नेता मान कर भाजपा के इस प्रयोग को सफल बना देंगे?यह ध्यान रखने की जरुरत है कि सैनी अगर गैर जाट चेहरा हैं तो वे गैर ब्राह्मण भी हैं, गैर दलित भी हैं, गैर गुर्जर भी हैं तो फिर ये जातियां कैसे उनके साथ जुड़ेंगी? क्या गैर जाट की भावना इतनी प्रबल है कि उसके विरोध में सारी जातियों किसी को भी नेता स्वीकार कर लेंगी? अगर बहुत सरल तरीके से यह मानें कि जिस जाति या समुदाय का व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है उसकी जाति उसके साथ ज्यादा मजबूती से गोलबंद होती है तो फिर इसी तर्क से यह मानना होगा कि दूसरी जातियां उससे दूरी बनाएंगी।इसलिए जाति का हिसाब कभी भी इतने सरल तरीके से काम नहीं करता है। **यह निजी विचार है।**

लोकसभा चुनावों में कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश में शून्य पर सिमट सकती है

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदले समीकरणों ने जहां दूसरे दलों के लिए नई संभावनाएं जगाईं, वहीं कांग्रेस को अपनों से मायूसी ही मिलती गई। 1984 में 51.03 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली कांग्रेस फिर ऐसे जनाधार को वापस नहीं हासिल कर सकी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस कांग्रेस का हमेशा अपर हैंड रहता था, वह अब दूसरों के रहम-ओ-करम पर राजनीति करने को मजबूर हो गई है। प्रदेश में ना उसका वोट बैंक बचा है, ना नेता और संगठन। हाँ, यदि हवा-हवाई बातों से पार्टी को फायदा हो पाता तो जरूर यूपी में कांग्रेस टॉप पर होती, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज का मतदाता अपने नेताओं पर बारीकी से नजर रखता है। इस कसौटी में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप और गांधी परिवार पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। कांग्रेस के विधान सभा और लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के आंकड़े भी चुनाव-दर-चुनाव उसके जनाधार खिसकने के साक्षी हैं। यह गिरावट 1984 के बाद चार दशक में आई है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 85 सीटों (तब उत्तराखंड की भी पांच सीटें शामिल) पर चुनाव लड़ी थी और 83 सीटों पर जीत हासिल की थी। भले ही तब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के साथ जनभावनाओं का ज्वार था, जिसके सहारे पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन के शिखर को छुआ। यह वह दौर था जब राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस का एकछत्र राज था और बीजेपी की एंट्री भर हुई थी, लेकिन उसकी राजनैतिक विचारधारा कांग्रेस से उलट थी। बीजेपी तुष्टिकरण की जगह हिन्दुत्व की बात करती थी। अयोध्या, काशी और मथुरा उसके एजेंडे में प्रमुख रूप से शामिल थे, जिससे कांग्रेस हमेशा किनारा करती रही थी। वहीं क्षेत्रीय दलों के रूप में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जातिवादी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। प्रदेश की राजनीति में बदले समीकरणों ने जहां दूसरे दलों के लिए नई संभावनाएं जगाईं, वहीं कांग्रेस को अपनों से मायूसी ही मिलती गई। 1984 में 51.03 प्रतिशत वोट हासिल करने वाली कांग्रेस फिर ऐसे जनाधार को वापस नहीं हासिल कर सकी। आज उसका जनाधार दो प्रतिशत में सिमट गया है।

दरअसल, प्रदेश में सपा व बसपा के उदय के साथ ही कांग्रेस पीछे होती गई और भाजपा की प्रखर हिंदुत्व वाली छवि ने उसकी राह और मुश्किल कर दी। ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कांग्रेस के परंपरागत वोटर माने जाते थे। सपा के उदय के साथ मुस्लिम कांग्रेस से छिटक कर उसके पाले में चला गया। बसपा ने कांग्रेस के दलित वोट बैंक पर कब्जा कर लिया। कांग्रेस से मोहभंग के बाद ब्राह्मणों ने भाजपा का दामन थाम लिया। वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग होने के बाद की बात की जाए तो कांग्रेस वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर लड़ी थी और 21 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछले ढाई दशक में यह कांग्रेस का सर्वाधिक उत्साहित करने वाला प्रदर्शन था। इसके पीछे कांग्रेस की मनरेगा व खाद्य सुरक्षा को लेकर नीतियों की बड़ी भूमिका मानी गई थी। कांग्रेस केंद्र में दोबारा सरकार बनाने में सफल हुई थी। इसके बावजूद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी साख को बचाए रखने में कामयाब नहीं रही।

उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने के लिय पार्टी ने कई प्रयोग भी किए। राहुल गांधी को यूपी में पैर पसारने के लिये खुली छूट दी गई, इसके नतीजे उत्साहवर्धक नहीं आये तो प्रियंका वाड्रा को प्रदेश का प्रभारी भी बनाया गया, लेकिन बूथ स्तर पर कमजोर हुई पार्टी के सामने कार्यकर्ताओं में पुराना जोश भरना सपना ही रहा। उधर, कांग्रेसी नेता आपस में टांग खिंचाई करते रहे, जिसकी वजह से पार्टी में अंतरकलह भी बढ़ता गया। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 2009 का अपना प्रदर्शन दोहराने को तरसती ही रही। नेहरू-गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश से गहरा रिश्ता होने के बाद भी पार्टी खोया दमखम नहीं जुटा सकी। पिछले चुनाव में कांग्रेस रायबरेली की एकमात्र सीट पर ही जीत का स्वाद चख सकी थी। पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी तक हार गये। जबकि रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी अबकी बार सदन में जाने के लिये राज्यसभा सदस्य बन चुकी हैं। इस बार वह भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन तलाशने के साथ ही परंपरागत सीट अमेठी व रायबरेली में अपनी साख को बचाए रखने की चुनौती से जूझ रही है।

इससे निपटने के लिए पार्टी सपा से गठबंधन के तहत उसके हिस्से आईं 17 सीटों पर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। प्रदेश मुख्यालय में वार रूम की स्थापना की गयी है और अमेठी व रायबरेली समेत 17 लोकसभा सीटों के 34 हजार बूथों पर एजेंट जुटाए जा रहे हैं। वार रूम के सदस्य संजय दीक्षित के अनुसार, 17 लोकसभा क्षेत्रों में अब तक 18 हजार बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए जा चुके हैं। शेष को भी जल्द नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा वार रूम के 10 डेस्क हेड भी बनाए गए हैं और सभी को आठ-आठ लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार सभी 80 लोकसभा सीटों पर बूथ स्तर पर संगठन को खड़ा किया जा रहा है। कुल मिलाकर यूपी से अपने नेताओं को संसद भेजने के लिये कांग्रेस को शून्य से सफर शुरू करना होगा और इसके लिये उसके सिर्फ17 प्रत्याशी मैदान में होंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन धर्म निभाते हुए यूपी में कांग्रेस को 80 में से 17 सीटें देने के लायक ही समझा है।

यह निजी विचार है।

बगिया के विष्णु, बिखेर रहे हैं खुशबू

नब्बे दिनों के विष्णु सरकार में सुशासन की दिखी लालिमा

जशपुर जिले के ग्राम बगिया के विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पद की शपथ 13 दिसंबर 2023 को ली थी। आदिवासी सरगुजा संभाग, जशपुर जिले के यह पहले व्यक्ति है, जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। बगिया से निकले इस लाड़ले विष्णु देव ने महज नब्बे दिनों में अपने अडिग निर्णय से तीन करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों के जीवन में एक खुशनुमा खुशहाली बिखेरने में सफलता अर्जित की है।

ईमानदार प्रयास नया मिसाल

वैसे तो किसी भी सरकार के लिए तीन माह का कार्यकाल बहुत ही कम होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णु के मन में कुछ नया करने की इच्छा शक्ति, जनसरोकार के लिए योजना बनाने की जुनून और ईमानदार प्रयास ने महज तीन माह, एक मिसाल बना और एक नया रिकॉर्ड कायम की।

गरीबों के चेहरे में खुशियां

मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ग्रामीणों के हित में निर्णय लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत प्रदेश के 18 लाख से अधिक आवासहीनों को पक्का मकान देने के निर्णय ने इन लाखों गरीबों के चेहरे में खुशियां बिखेर दीं। प्रदेश के करीब 68 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को अगले पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न देने के फैसले से इन परिवारों को भरपेट भोजन भी मिलेगा।

युवाओं के भविष्य सुरक्षित

प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षा प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा-2021 की शिकायतों की जांच सीबीआई से जांच कराने व यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बेरोजगारों के हित में फैसला लेते हुए शासकीय सेवा में भर्ती हेतु स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में दिसंबर 2028 तक छूट दी गई है।

किसानों के पीड़ा को किया दूर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव दूरस्थ आदिवासी अंचल से होने के साथ एक मंजे हुए किसान पुत्र भी हैं, इसीलिए किसानों की पीड़ा को वे बेहतर समझते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर राज्य के किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस के भुगतान की गारंटी को पूरा करते हुए 13 लाख किसानों को 3 हजार 716 करोड़ रूपए का भुगतान की गई।

सबसे बड़ी राशि किसानों के खातों में

अपने वादे के अनुरूप किसानों के हित में खरीफवर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी की गई, 24 लाख 72 हजार किसानों से 144.92 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान खरीदी की गई और अन्नदाताओं को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान भी किया गया तो 12 मार्च को ''कृषक उन्नति योजना'' के तहत समर्थन मूल्य की अंतर राशि 13 हजार 320 करोड़ रूपए अन्नदाताओं के खाते में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने डीबीटी के माध्यम से पंहुचाने का साहसिक कार्य किए हैं।

आदिवासियों के हित में बड़ा निर्णय

प्रदेश के लाखों आदिवासी भाई-बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए तेंदूपत्ता संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक दर 4 हजार रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रूपए किया गया साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय भी लिए हैं।

आस्था-विश्वास व भावनाओं का रखा ध्यान

प्रदेशवासियों के विश्वास व आस्था की भावनाओं को सम्मान देते हुए विष्णु सरकार ने रामलला दर्शन (अयोध्या धाम) योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रदेश के 18 से 75 आयु वर्ग के पात्र हितग्राहियों को अयोध्या धाम दर्शन के लिए विशेष ट्रेन शुरू की है, वहीं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर नगरी राजिम के वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ (कल्प) की शुरूआत भी की।

मातृ शक्ति का किया वंदन

डबल इंजन वाली विष्णु देव सरकार ने मोदी की गारंटी पर मुहर लगाते हुए महतारी वन्दन योजना के तहत प्रदेश के 70 लाख से अधिक विवाहित महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा विश्वनाथ की धरती काशी से शुभारंभ किए और प्रथम किस्त की राशि करीब 700 करोड़ रुपए इन महिलाओं के खाते में अंतरित हुई। विष्णुदेव साय सरकार ने एक अहम फैसले लेते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमोदन किया है। साथ ही प्रदेश की आधी आबादी यानी माताओं एवं बहनों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि कोई भी नई मदिरा दुकान नहीं खोली जाएगी। संवेदनशील मुख्यमंत्री साय ने लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की भावनाओं का सम्मान करते हुए 430 लोकतंत्र सेनानियों-आश्रितों को सम्मान निधि देने का निर्णय लिया।

सचमुच 13 दिसम्बर 2023 छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसे नाम दर्ज हुए हैं जो बरसो तक याद रखी जाएगी। महज 90 दिनों में विष्णु के सुशासन की लालिमा प्रदेशवासियों को देखने को मिली रही है।

-एल.डी.मानिकपुरी,

इजराइल ने अपना कमाया सब गंवाया!

श्रुति व्यास

कौन सोच सकता था कि इजरायली इतने बेरहम, इतने ज़ालिम हो सकते हैं? और ऐसा मैं भावनाओं में बहकर नहीं कह रही हूं। एक वक्त के इजराइल के मसीहा बेंजामिन नेतन्याहू ने जब से हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा है (जो दरअसल गाजा निवासियों और फिलिस्तीनियों का कत्लेआम है) तबसे इजराइल एक अपराधी, और नेतन्याहू एक हत्यारा लगने लगे हैं। और यद्यपि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर नेतन्याहू के कारण सभी यहूदी खराब लगते लगे हैंयुद्ध शुरू हुए छह महीने गुज़र चुके हैं। क्रिसमस के बाद अब रमजान आ गया है। और तब से लेकर अब तक कत्लेआम जारी है। गाजा पर मौत की काली छाया मंडरा रही है। बच्चे भुखमरी का शिकार हो रहे हैं, महिलाओं का खून बहाया जा रहा है और ब्रेड के एक टुकड़े के लिए भाई, भाई की हत्या कर रहा है। युद्धविराम प्रेस और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा पश्चिम की आलोचना से बचने के लिए रचा गया एक भ्रमजाल बनकर रह गया है ङ्क जैसे बच्चे का ध्यान हटाने के लिए लालीपाप।हाल के एक वीडियो में इजराइलियों के एक समूह ङ्क जिसे चैनल ने क्रुद्ध बताया है मगर असल में जो क्रूर हैं ङ्क गाजा में खाद्यान्न एवं अन्य सहायता सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को रोकने की कोशिश करते हुए दिखाया गया। वे पुलिस की नाकाबंदी के आगे गाजा भेजी जाने वाली राहत सामग्री को रोकने के लिए अपनी नाकाबंदी कर रहे थे।इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व तसाव-9 नामक एक संगठन कर रहा है जो पूर्व रिजर्व सैनिकों, अपहृत लोगों के परिवारजनों और फिलिस्तीन में बसाए गए लोगों का समूह है। शिशुओं को अपने शरीरों से बांधे युवा पुरूष और महिलाएं, और उनके पीछे-पीछे दौड़ते बच्चे, यह मानते हैं कि इन ट्रकों में खाना नहीं बल्कि बंदूक की गोलियां हैं। वे सोचते हैं कि यदि गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं तो हमास बंधकों को रिहा क्यों नहीं कर रहा है? इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीटयूट द्वारा करवाई गई एक रायशुमारी से पता चलता है कि दो-तिहाई यहूदी इजरायली, गाजा में मानवीय सहायता पहुँचाने के विरोध को उचित मानते हैंयह किसने सोचा था कि इतिहास में एक ऐसा दिन आएगा जब दुनिया यहूदियों की इतनी निर्दयता, इतनी निर्ममता देखेगी। यह भविष्यवाणी किसने की होगी कि एक ऐसा दिन आएगा जब लोग देशों की सीमाओं, नस्ल और जाति की सीमाओं के परे इजराइल और यहूदीवाद के विरोधी हो जाएंगे। आखिर एक करोड़ से भी कम जनसंख्या वाला यह छोटा सा देश, जिसे सारी दुनिया चाहती थी, जो मध्यपूर्व में लोकतंत्र का चमकीला सितारा था, इतना जंगली और पत्थरदिल क्यों हो गया?इजराइल के प्रति सहानुभूति और करूणाभाव समाप्त होता जा रहा है। सात अक्टूबर को इजराइल की तकलीफसारी दुनिया सांझा कर रही थी, सारी दुनिया दुखी थी, सबकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये सारे अहसास अब खत्म हो चुके हैं। आंसुओं की जगह तिरस्कार भाव ने ली है। मानव समुदाय विभाजित हो गया है।

खास खबर

कार से बरामद हुए 18 लाख 62 हजार रूपये नगद

रायपुर (ए.)। जिले की मंदिर हसौद थाना पुलिस एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम ने थाना क्षेत्रांतर्गत टोल नाके के पास से वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 18 लाख रूपये से ज्यादा नगदी रकम बरामद किया है।

मिली जानकारी के अनुसार आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट एवं थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत स्थित टोल नाका पास वाहनों की आकस्मिक चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान चारपहिया वाहन क्रमांक ओडी/15/यू/9001 को चेक करने पर बैग में लाखों रूपये नगदी रकम रखा होना पाया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा वाहन में सवार व्यक्ति से लाखों रूपये नगदी रकम के संबंध में पूछताछ करने एवं वैध दस्तावेज की मांग करने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत न कर टीम के सदस्यों को लगातार गुमराह किया जा रहा था। जिस पर टीम ने उक्त वाहन चालक के पास रखें 18,62,200 रूपये नगदी रकम को धारा 102 जा.फौ. के तहत थाना मंदिर हसौद में जप्त किया है।

8 लाख का ईनामी नक्सली पकड़ाया

बीजापुर (ए.)। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस 8 लाख का इनामी नक्सली कमांडर मद्देड दलम सुधाकर उर्फ़ उण्डम को गिरफ्तार किया है। यह नक्सली थाना तरलागुडा पर हमला करने के साथ-साथ हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण, आगजनी, बलवा जैसे कई घटनाओं मे शामिल था।

मिली जानकारी के अनुसार, जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत छ्क्रत्र और कोबरा 210 और थाना बासागुड़ा की संयुक्त टीम इलाके में गश्त के लिए निकली थी। तभी अचानक सर्चिंग पार्टी को यहां इसके होने की सूचना मिली। जिसके बाद घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के विरुद्ध कई थानों में 108 वारंट लंबित है और वह कई बड़ी वारदातों में भी शामिल रहा है।

सड़क हादसा: एक्सीडेंट में तीन पश्चिम बंगाल के मजदूरों की मौत

रायपुर (ए.)। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हुए सड़क हादसे में तीन युवकों ने अपनी जान गवां दी है। इस भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। यह तीनों युवक पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जो कि छत्तीसगढ़ के धमतरी में मजदूरी करने का काम करते थे।

धमतरी जिले के पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत सांकरा गांव में बुधवार की शाम एक सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। मृतक युवकों का नाम शरीफुल हक जिसकी उम्र 21 साल, अब्दुल रहीम जिसकी उम्र 42 साल और कमालीन जमाल जिसकी उम्र 26 साल बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह तीनों युवक पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के निवासी थे। घटना की जानकारी को लेकर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि तीनों युवक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। मजदूरी करने के उद्देश्य से यह तीनों छत्तीसगढ़ के धमतरी पहुंचे हुए थे। भोथली बोडरा में रहकर हाई टेंशन तार लगाने का यह तीनों काम पिछले कुछ मन से कर रहे थे। बताया जा रहा है कि शाम को दो पहिया वाहन से यह तीनों गांव से सिहावा सांकरा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया और उनकी जान चली गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

युवक ने लगाई फांसी

अंबिकापुर (ए.)। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मंगलवार देर रात एक युवक ने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि युवक घोषित बदमाश था और पुलिस उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। घर लौटने के बाद उसने अपने कमरे में फांसी लगा ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू की। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस फिंगर प्रिंट के नाम उसे थाने ले गई थी। जहां उसे प्रताड़ित किया और धमकी देकर रुपयों की मांग करी। इस वजह से उसने यह कदम उठाया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस बदमाशों का फिंगर प्रिंट ले रही है।

फेरी वाले, किराएदारों के कागजातों के आधार पर उनके बारे में जानकारी ली जा रही

कोरबा पुलिस कर रही बाहर से आकर रहने वालों की सघन जांच

रायपुर (ए.)। पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशनएवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान एवं नेहा वर्मा के मार्गदर्शन में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारी एवं थाना-चौकी क्षेत्र अंतर्गत होटल, लॉज, फेरी करने वाले, किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों का जांच अभियान चलाया गया।

पुलिस टीम के द्वारा होटल, लॉज संचालकों को स्पष्ट हिदायत दिया गया है कि होटल, लॉज में रुकने वाले व्यक्तियों की सूची बनाकर थाने में विधिवत तरीके से दिया जाए और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल लॉज में रुका हो उसकी जानकारी भी तुरंत नजदीकी थाने में दिया जाए। पुलिस टीम के द्वारा संदिग्धों और मुसाफिरों की जांच को लेकर क्षेत्र में घूम-घूम कर सामानों की फेरी करने वाले, सडक किनारे जडी बूटी, कपड़े, खिलौने बेचने वाले तथा गैस चूल्हा आदि रिपेयर करने वालों को पुलिस थाना में तलब कर उनके वास्तविक पते, वर्तमान गतिविधियों तथा मुसाफिरी दर्ज कराने की जानकारी लिया गया। कुछ फेरीवालों ने थाने में मुसाफिरी दर्ज नहीं कराये थे उनकी मुसाफिरी दर्ज करायी गई। कोरबा पुलिस के द्वारा मुसाफिर चेक करते हुए 1990 लोगों को चेक किया गया, 597 किरायेदारों को तस्दीक़ किया गया, संदिग्ध अजनबी (एस एस रोल) के तहत 2026 लोगों को चेक किया गया एवं कदाचारी (बी सी रोल) के तहत 39 लोगों को चेक किया गया है। 2026 व्यक्तियों में से 164 उत्तर प्रदेश, 216 बिहार झारखंड, 94 महाराष्ट्र, 89 राजस्थान, 85 हरियाणा, 142 उड़ीसा जैसे राज्यो को एवं 1236 अन्य दीगर जिलों को जारी किया गया है एवं उनके राज्य के नजदीकी थाने में संपर्क करके उनके बारे में जानकारी लिया गया।

थाना प्रभारियों द्वारा फेरीवालों को आपराधिक गतिविधियों से दूर रहकर विधिवत जीवन व्यतीत करने की समझाइश दी गई है और गलत काम धंधों में पाए जाने से कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर छोड़ा गया है। बाहरी व्यक्तियों को किराए पर रखने वाले मकान मालिकों एवं किराएदारों का सत्यापन किया गया और किराएदारों की सूची तैयार की गई। सत्यापन कार्य में लगे पुलिस के द्वारा किराएदारों के आईडी लेकर चेक किये और उनके काम काज की जानकारी लिया गया तथा उन्हें अवैधानिक गतिविधियों से दूर रहने की समझाइश दिये।

पुलिस की टीम के द्वारा मकान मालिक की व्यक्तिगत जवाबदारी है कि वह थाने में किराएदार की सूचना दें। मकान मालिकों को हिदायत दिया गया कि मकान किराये पर देने से पूर्व अनिवार्य रूप से किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन कराये अगर कोई मकान मालिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोरबा पुलिस की अपील है कि सभी अपने किराएदार और नौकरों का संबंधित थाने में जाकर अनिवार्य रूप से वेरिफिकेशन अवश्य करावें।

थाने में पुलिस टीम के द्वारा पार्षदों एवं ठेकेदारों की मीटिंग लिया गया जिसमें पार्षदों को बताया गया कि आपके क्षेत्र में मकान मालिक के घर पर किराएदार रखना पर उसका सत्यापन आवश्यक रूप से करवा ले एवं संदिग्ध लोग दिखे तो उसके बारे में पुलिस टीम को सूचित किया जाए, मीटिंग में ठेकेदारों को बताया गया कि मजदूरों को काम पर रखने से पहले उनकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

मुंबई से आया प्रेमी, हत्या कर भागा यूपी

पुलिसकर्मी की पत्नी के मर्डर का खुला राज, सोशल मीडिया पर बनाया बॉयफ्रेंड और वही निकला कातिल

रायपुर (ए.)। राजधानी रायपुर में 9 दिन पहले पुलिसकर्मी की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला का बॉयफ्रेंड ही निकला। मूलत: यूपी के भदोही गांव का रहने वाला है और पुलिस उसे वहीं से गिरफ्तार कर लेकर पहुंची। गुरुवार को पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए हत्या की वजह भी बताई। यह पूरा मामला विधानसभा थाना क्षेत्र का है।

बता दें विधानसभा थाना पुलिस को 5 मार्च की देर रात सूचना मिली कि आमासिवनी इलाके के पुलिस कॉलोनी में पुलिस कर्मी की पत्नी की हत्या हो गई है। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी थी। दरअसल मृतका के पति ने उसे फोन किया तो उसने रिसीव नहीं किया तो उसने पड़ोसियों को कॉल कर देखने कहा था। पड़ोसियों ने देखा तो खून से लथपथ लाश पड़ी थी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेजा। मृतिका जॉली सिंह का पति शिशुपाल सिंह सुकमा पुलिस में पदस्थ है। वह डॉग हैंडलर का काम करता है। घटना की सूचना के बाद मृतिका का पति रायपुर पहुंचा। इसके अलावा परिवार वाले भी यूपी से रायपुर पहुंचे थे।

पुलिस क्वार्टर में पुलिस कर्मी की पत्नी की हत्या पुलिस के लिए बड़ा सवाल था और एसपी के निर्देश पर आरोपी की तलाश की जा रही थी। पुलिस ने जब घटना स्थल की जांच की तो मौके पर मुंबई से रायपुर की फ्लाइट टिकट मिली। इसके अलावा पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। फ्लाइट टिकट के जरिए पुलिस ने सीसी टीवी कैमरे में एक डिलीवरी बॉय को संदिग्ध पाया और उसकी तलाश शुरू की। लगभग 9 दिन की मेहनत के बाद पुलिस का सफ्लता मिली और आरोपी को यूपी के भदोही गांव से गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया।

4 साल पहले हुई थी जान पहचान

पुलिस ने इस मामले में जय सिंह उर्फ राहुल को गिरफ्तार किया। दरअसल राहुल यूपी के भदोही का रहने वाला है और मुंबई कि किसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। मृतका मृतका जॉली सिंह से उसकी 4 साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म टिकटॉक के जरिए हुई थी। दोनों साथ में मिलकर रील्स बनाया करते थे। यहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ी। जॉली अपने पुलिसकर्मी पति से अलग आमासिवनी के पुलिस क्वार्टर में रहती थी। वहीं आरोपी जयसिंह भी शादी शुदा है। जॉली से मिलने वह रायपुर अक्सर डिलीवरी बॉय के गेटअप में ही आता था।

हत्या के दिन फ्लाइट से पहुंचा था रायपुर

पुलिस ने बताया कि आरोपी राहुल हत्या वाले दिन फ्लाइट से रायपुर पहुंचा। डिलीवरी बॉय बनकर पुलिस क्वार्टर जॉली सिंह से मिलने पहुंचा। जॉली सिंह सिंह अपने प्रेमी जय सिंह से शादी करना चाहती थी। वहीं जय सिंह पहले से शादीशुदा होने के कारण इसके लिए तैयार नहीं था। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ा तो जय सिंह ने जॉली को धक्का दिया जिससे वह गिर गई। इसके बाद उसने पास में रखी कैंची से उसे गले में वार कर दिया। इस वार के कारण जॉली सिंह की मौत हो गई। इसके बाद जय सिंह वहां से फ्ऱार हो गया।

फ्लाइट टिकट से आरोपी तक पहुंची पुलिस

जांच के दौरान पुलिस को केवल फ्लाइट टिकट ही मिली थी। आरोपी जय सिंह मुंबई से फ्लाइट से आया और रायपुर एयरपोर्ट से जॉली सिंह के घर पहुंचा। हत्या के बाद वह इलेक्ट्रिक वाहन से रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से पुरी-एलटीटी एक्सप्रेस में बिना टिकट बैठा और भुसावल तक गया। वहां से कमायनी एक्सप्रेस में अपने गांव भदोही पहुंचा।सारी जानकारी जुटाने पुलिस ने उसे वहीं से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह आगे नेपाल भागने के भी फ्रिाक में था। पुलिस को मुंबई व रायपुर एयरपोर्ट की सीसी टीवी फुटेज में वह डिलीवरी बॉय के कपड़ों दिखा। पुलिस क्वार्टर के पास रहने वालों ने भी जॉली के घर ऐसे ही किसी युवक के आने की बात बताई थी। इसी आधार पर पुलिस आरोपी जयसिंह तक पहुंची और उसे भदोही से पकड़कर लाया गया।

बाइक सवारों को समझाना पुलिसकर्मियों को पड़ा भारी

जगदलपुर (ए.)। जगदलपुर के नगरनार थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर और प्रधान आरक्षक को बाइक सवार युवकों को सही से बाइक चलाने के लिए समझाना महंगा पड़ गया। तीन युवकों ने एसआई व प्रधान आरक्षक का रास्ता रोककर पहले तो गाली गलौज की। उसके बाद अपने पास रखे चाकू को दिखाने के साथ ही हेलमेट से पिटाई कर फ्ऱार हो गए। इस घटना में दोनों पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की रिपोर्ट नगरनार थाना में दर्ज कराया गया है। जहां आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है।

बताया जा रहा है कि ये युवक जब तेजी से बाइक चलाते हुए पुलिसकर्मियों की साइड से निकले तो सब इंस्पेक्टर रत्नेश सेठिया इन युवकों को रोककर नाम पता पूछताछ कर फ्रि से इस तरह से वाहन न चलाने की बात कहते हुए समझाने लगे, जिसपर युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ बहसबाजी की और वहां से चले गए।

जिसके बाद बाद युवकों ने दोनों पुलिसकर्मियों को बीच रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज करते हुए मारपीट की। तीन युवक नितिश, अजय ऊर्फ अज्जू और अनिल ने चाकू दिखाते हुए धमकाया भी और हेलमेट से वार कर पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

तेज रफ्तार वाहन ने बच्ची को रौदा, मौत

कवर्धा, । भोरमदेव थाना क्षेत्र से हिट एंड रन का मामला सामने आया है. जहां एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 3 साल की बच्ची को रौंद दिया. घटना के बाद बोलेरो चालक वहां से भाग खड़ा हुआ. फ्लिहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है. घटना में घायल बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई है. ये हादसा तब हुआ जब बच्ची नाना-नानी के साथ भोरमदेव मंदिर दर्शन करके लौट रही थी. मृत बच्ची का नाम सिया ठाकुर बताया जा रहा है।

जनप्रतिनिधियों को आवंटित शासकीय वाहन को वापस लेने आदेश जारी

मनेन्द्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा आज 16 मार्च 2024 को हो चुकी है, एवं आदर्श आचार सहिंता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 की प्रक्रियाओं के समापन तक के लिए केन्द्रीय, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एंव अन्य जन प्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के निर्वाह के लिए आबंटित शासकीय वाहनों का दुरूपयोग रोकने के लिए वापस लेना आवश्यक है। अतः केन्द्रीय, राज्य सरकार के सार्वजनिक, उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधि, उन्हें उनके पदीय दायित्वों के निर्वाह हेतु आबंटित वाहन, लोकसभा निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक के लिए संबंधित कार्यालय के सक्षम शासकीय प्राधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को तत्काल वापस करें।

अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध

रायपुर (कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु समस्त अधिकारी-कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि वे कलेक्टर या जिला निर्वाचन अधिकारी के पूर्वानुमति के न तो अवकाश पर रहेंगे और ना ही मुख्यालय छोड़ेंगे। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार जिला स्तर पर तथा जिले अंतर्गत समस्त शासकीय एवं राज्य शासन के विभागीय इकाईयों/उपक्रमों के अमले के अवकाशों की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।

रायपुर में शराब तस्करी के सिंडीकेट का भंडाफोड़, महिला समेत छह गिरफ्तार

■ ओडिशा से रायपुर की ओर आने वाली बस में कर रहे थे अवैध रूप से शराब परिवहन

रायपुर (ए.)। रायपुर पुलिस ने शराब तस्करी के एक सिंडीकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत छह तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 113 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ सात मोबाइल जब्त किया है। पकड़े गए तस्कर बस में शराब से भरा कार्टून रखकर कोलकाता से ओडिशा के रास्ते रायपुर में शराब खपाने ला रहे थे।इनमें तीन तस्कर ओड़िशा और तीन रायपुर के रहने वाले है।

मंदिर हसौद पुलिस थाना प्रभारी रोहित मालेकर ने बताया कि बुधवार को सूचना मिली थी कि ओडिशा से रायपुर की ओर आने वाली बस ग्रांड स्लीपर में अवैध रूप से शराब परिवहन किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस की संयुक्त टीम ने मंदिर हसौद टोल नाका के पहले चेकिंग पाइंट लगाकर वाहनों की जांच शुरू की।इसी दौरान ग्रांड स्लीपर बस को आता देखकर रूकवाया गया।

बस में अलग-अलग कार्टूनों में पैक कर करीब 113 बोतल अंग्रेजी शराब मिला। बस चालक ओड़िशा के जयंतसिंहपुर जिले के बनवालीपुर पोष्ट मोहिजीनपुर निवासी प्रेमाचंद परीडा(65), ओडिशा के पुरी जिले के आईटोटा थाना उमरपाडा निवासी कंडेक्टर कैलाश चंद्र नायक(62) शराब से संबंधित वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि शराब की बोतलों से भरा कार्टून बनवालीपुर, ओडिशा के खुरदाराज जिले के खुरदा थाना बुलोगढ निवासी प्रशांत कुमार बरार(33) ने रायपुर की एक पार्टी को देने के लिए रखवाया था।

पुलिस टीम ने इसके आधार पर श्रीजी वंद्रावन कालोनी बी-3 चौथा प्लोर अमलीडीह निवासी गगनप्रीत सिंह कौर पति अमन उर्फ शरणजीत सिंह(34) को पकड़ा। पूछताछ में उसने शराब को कोलकाता निवासी गुड्डु सिंह से ओडिशा के रास्ते प्रशांत कुमार बरार के माध्यम से रायपुर में मंगवाकर अपने पति सरणजीत होरा और श्यामनगर,तेलीबांधा निवासी भाई जग साहेब सिंह (26) के जरिए ग्राहकों को बेचना बताया। गगनप्रीत सिंह कौर की निशानदेही पर सरणजीत सिंह होरा, जग साहेब सिंह को कार के साथ और प्रशांत कुमार बरार को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि फरार गुड्डु सिंह की तलाश की जा रही है।

आबकारी विभाग ने जब्त की पड़ोसी राज्य की अवैध शराब

रायपुर (ए.)। आबकारी विभाग रायपुर ने अवैध मदिरा संग्रहण-परिवहन पर कार्यवाही करते हुए मध्यप्रदेश की रेड लेबल स्कॉच व्हिस्की सहित कुल 153.04 बल्क लीटर कीमती लगभग 135000/- रूपये अवैध मदिरा जप्त कर 20 आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण कायम कर गैर जमानतीय धाराओं में 9 आरोपियो को जेल भेजा गया, साथ ही अवैध मदिरा परिवहन में 4 दोपहिया वाहन भी जप्त किया गया। जिले की आबकारी टीम द्वारा छापामार कार्यवाही कर आरोपी से जप्त कर 34(2), 36, 59(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है।

आचार संहिता लागू होते ही हटने लगी प्रचार सामग्री

रायपुर । ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के निर्देश पर आज से आचार संहिता लगते ही संपत्ति विरूपण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है । इसके तहत 24 घण्टे के भीतर शासकीय संपति से और 48 घण्टों के भीतर सार्वजनिक स्थानों से प्रचार-प्रसार की सामग्री हटाई जानी है। नगरीय निकायों में और जनपद पंचायतों में टीम बनाकर यह कार्रवाई आज रायपुर ज़िले के चारो ब्लॉक धरसीवां ब्लॉक,आरंग ब्लॉक,तिल्दा ब्लॉक एवं मंदिर हसौद ब्लॉक में प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही नगरीय निकायों में भी यह कार्यवाही की जा रही है। शासकीय प्रचार प्रसार वाले होर्डिंग को कवर किया गया है ,वही वॉल पेंटिंग की पोताई की गई है।

लोकशक्ति www.lokshakti.in

अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिए निर्देश

निर्वाचन संबंधी शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित दूरभाष क्रमांक 07817-222123 पर की जा सकती है शिकायत

लोकसभा निर्वाचन 2024: कलेक्टर ने कंट्रोल रूम, सी-विजिल कक्ष का किया निरीक्षण

जांजगीर-चांपा

कलेक्टर श्री आकाश छिकारा ने आज लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए कंट्रोल रूम, सी-विजिल कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान कंट्रोल रूम, सी-विजिल कक्ष से अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कंट्रोल रूम में अधिकारी-कर्मचारियों को निर्वाचन से संबंधित प्राप्त शिकायतों को संबंधित तक पहुंचाएं ताकि पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ शिकायतों का निराकरण त्वरित किया जाए। कलेक्टर ने सी विजिल एप्प के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की कुशलतापूर्वक त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री एस पी वैद्य, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल कुमार रावटे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मड़ावी सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। जांजगीर-चांपा 16 मार्च 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय जांजगीर-चांपा में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। यह कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के 24 घंटे संचालन के लिए अधिकारी, कर्मचारियों की तैनाती की गई है। उक्त कंट्रोल रूम में स्थापित दूरभाष का क्रमांक 07817-222123 है। यहां सी-विजिल ऐप, एनजीपीएस, सीपीएस, ऑफ्लाइन और टेलीफोन के माध्यम से शिकायत की जा सकती है।

लोकसभा आम निर्वाचन 2024 - जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई

जांजगीर-चांपा लोकशक्ति। लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु आज 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शासकीय एवं सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर-एसपी ने ली राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक

कलेक्टर ने ली आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में प्रेसवार्ता

निर्वाचन कार्यक्रम व आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तार से दी जानकारी

जांजगीर-चांपा 16 मार्च 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा एवं पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। लोकसभा निर्वाचन 2024 के नाम निर्देशन से लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा में निर्वाचन की प्रक्रिया तीसरे चरण में होगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन प्रारंभ होने की तिथि 12 अप्रैल से, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल, नाम निर्देशन की संवीक्षा तिथि 20 अप्रैल, अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल, मतदान की तिथि 7 मई और मतगणना की तिथि 4 जून निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र अवकाश दिवस को छोड़कर प्राप्त कर सकते है।

कलेक्टर ने राजनीतिक दलों को चुनावी बैठक, रैली, जुलूस तथा अन्य कार्यक्रम के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही प्रचार-प्रसार सामग्री में मुद्रक, प्रकाशक और संख्या का उल्लेख भी किया जाना भी जरूरी होगा। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को सुविधा एप की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर डीएफओ श्रीमती प्रियंका पांडेय, अपर कलेक्टर श्री एस पी वैद्य, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गोकुल कुमार रावटे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मड़ावी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा ने प्रेसवार्ता को संबोधित लोकसभा निर्वाचन 2024 की समय अनुसूची की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन से संबंधित आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई है। कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही जिला जांजगीर-चांपा के सम्पूर्ण क्षेत्र में संपत्ति विरूपण के तहत होर्डिंग, बैनर पोस्टर, दिवाल लेखन को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही सीविजिल ऐप, कंट्रोल रूम एवं एमसीएमसी टीम का गठन किया गया है। इस अवसर पर विभिन्न मीडिया संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहें।

तैयारियों का जायजा लेने स्ट्रांग रूम पहुंचे कलेक्टर-एसपी

मतगणना कक्ष व मतदान सामग्री वितरण कार्ययोजना के संबंध में अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जांजगीर-चांपा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आकाश छिकारा एवं पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला ने आज जांजगीर के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम के निरीक्षण में पहुंचे। यहां उन्होंने निर्वाचन के लिए सुविधाओं और सुरक्षा के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री एस पी वैद्य, अपर कलेक्टर श्रीमती लवीना पांडेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार जायसवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निशा नेताम मड़ावी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री छिकारा ने स्ट्राँग रूम का निरीक्षण कर वहां ईवीएम को रखने की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने ईवीएम, सामग्री वितरण के लिए आवश्यक मूवमेंट, मतदान दलों के वाहन पार्किंग के संबंध में जानकारी लेते हुए जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

खास खबर

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही निर्वाचन संबंधी समितियां शुरू करेंगी अपना काम - डॉ गौरव सिंह

रायपुर। लोकसभा निर्वाचन के लिए आचार संहिता लागू होते ही विभिन्न निगरानी समितियां सक्रिय होंगी। मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति, आदर्श आचार संहिता समिति तथा निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण समिति निर्वाचन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर बारिकी से नजर रखेंगी और सावधानियां बरतेंगी। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन के तैयारियों की समीक्षा बैठक में यह बात कही। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गौरव सिंह ने कहा कि जैसे ही राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा करेगा, वैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होना मानी जाएगी। सभी अधिकारी इसका पालन कराना सुनिश्चित करें। सभी अधिकारी निष्पक्ष होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि आचार संहिता लगते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत 24 घण्टे के भीतर शासकीय कार्यालयों से और 48 घण्टों के भीतर सार्वजनिक स्थानों से प्रचार-प्रसार की सामग्री हटा दी जाएगी। नगरीय निकायों में और जनपद पंचायतों में टीम बनाकर यह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विरूपण की कार्रवाई गंभीरतापूर्वक हो। इसमे किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें। नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा, एडीएम देवेन्द्र पटेल, कीर्तीमान राठौर सहित सभी जोन कमिश्नर उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ के दो आईपीएस अफसरों का केंद्र में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर मनोनयन

रायपुर। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के 2 आईपीएस सहित 47 आईपीएस अफसरों को आईजी इम्पैनल किया है। 2005 बैच के अमरेश मिश्रा और राहुल भगत केंद्र में इंस्पेक्टर जनरल इम्पैनल हो गये हैं। बता दें कि दोनों आईपीएस अफसरों अभी छत्तीसगढ़ में अहम ओहदा संभाल रहे हैं। जानकारी के अनुसार आदेश आज जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार रायपुर के आइपीएस अमरेश मिश्रा को आईजी पद पर इमपैनलमेंट किया गया है, वे रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हैं। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अंवेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो का पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। इसी तरह आइपीएस राहुल भगत को भी आईजी पद पर इमपैनलमेंट किया गया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राहुल भगत सीएम सचिवालय के सचिव हैं तथा नए विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

कार्यकर्ता पद के लिए मंगाये गये दावा-आपत्ति आवेदन

रायगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना रायगढ़ (शहरी)अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पूछापारा वार्ड क्रमांक 11, आंगनबाड़ी केन्द्र गौशाला पारा वार्ड क्रमांक 14, आंगनबाड़ी केन्द्र झोपड़ीपारा वार्ड क्रमांक 35 एवं आंगनबाड़ी केन्द्र राजीवगांधी नगर ए वार्ड क्रमांक 36 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद के लिए जारी प्राविधिक/अनंतिम मूल्यांकन पत्रक पर दावा-आपत्ति आवेदन मंगाये गये है। आवेदिका 18 मार्च से 2 अप्रैल 2024 सायं 5.30 बजे तक सीधे परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना, रायगढ़ (शहरी) में दावा-आपत्ति आवेदन जमा कर सकते है।

समाज और मानवता के लाभ के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करें - राज्यपाल हरिचंदन

22 मेधावी विद्यार्थियों को दिया गया स्वर्ण पदक

रायपुर। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन एमिटी विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों से समाज व समग्र मानवता के लाभ के लिए अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने हेतु संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज के गरीब व वंचित लोगों के लिए विद्यार्थियो को काम करना है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्री हरिचंदन ने 22 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 16 को रजत पदक और 5 को कांस्य पदक प्रदान किए। समारोह में वर्ष 2023 बैच के 681 विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां वितरित की गई। विश्वविद्यालय द्वारा डीएआरई के सचिव और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग नई दिल्ली के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई । कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने की।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह का यह दिन विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण चरण है। सभी ने अपने विषयों में ज्ञान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि डिग्रियों से अधिक, जो ज्ञान और मूल्य यहां हासिल किया है वह पूरे जीवन में उनका मार्गदर्शन करेगा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा है। आज दुनिया की नजरों में भारत के प्रति धारणा उल्लेखनीय रूप से बदल गई है, कई देशों के साथ आपसी सहयोग के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सामने आया है। इस देश के युवा के रूप में हमारी अर्थव्यवस्था के विकास और राष्ट्र के समग्र विकास के अग्रदूत बनने जा रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि जीवन के हर विषय में मूल्य-आधारित शिक्षा, रचनात्मकता, नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम से ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और गरीबी, बीमारियों, बेरोजगारी, भूख और पर्यावरणीय चुनौतियों सहित कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।

राज्यपाल ने कहा कि यह गर्व विषय है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में जगह बनाने के लिए लगातार प्रयास किए। शैक्षणिक पाठ्यक्रम गतिशील होना चाहिए, यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बराबर होना चाहिए और उद्योग-केंद्रित और अनुसंधान उन्मुख होना चाहिए। सरकार ने वित्तपोषण और उद्यमिता तथा नौकरी सृजन को बढ़ावा देने के लिए 'स्टार्ट-अप इंडिया' अभियान शुरू किया है। राज्यपाल ने विद्यार्थियो से उद्यमी बनने का आग्रह किया।

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अपने संबोधन में विद्यार्थियो से आग्रह किया कि वे एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने तक सीमित न रहे बल्कि अपने लिए खुला आसमान रखें और ऊंची उड़ान भरे । कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा करें। समारोह को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष प्रो. कर्नल उमेश कुमार मिश्रा भी ने भी संबोधित किया। कुलाधिपति डॉ. डब्ल्यू सेल्वामूर्ति ने विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इस अवसर पर विश्विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. अशोक के चौहान, अध्यक्ष डॉ. असीम के चौहान, कुलपति डॉ. पियूष कांत पाण्डे, फैकल्टी मेंम्बर्स, डीन, प्राध्यापक, छात्र-छात्राएं एवं उनके परिजन भी उपस्थित थे।

अंतिम व्यक्ति तक मिले योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ - मंत्री देवांगन

रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग और श्रम मंत्री एवं मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन हो और उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए।

उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करते हुए जनहित के कार्य करने प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब और आम किसानों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले, जिससे बेहतर विकास होगा और जिले का नाम रोशन होगा। प्रभारी मंत्री देवागंन ने विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक के दौरान पात्र हितग्राहियों को अच्छी गुणवत्ता का चावल उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास में भर्ती के संबंध में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को फसल बीमा योजना का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने तथा जल जीवन मिशन के कार्य को मिशन मोड में पूरा करने के लिए कहा। बैठक में मुंगेली विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले ने ट्रांसफार्मर की उचित व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए, ताकि जिले में कम वोल्टेज की समस्या ना हो, उन्होंने स्वीकृत निर्माण कार्यों को भी तत्काल शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी बढ़िया कार्य कर रहे हैं, आगे भी इसी तरह कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलेक्टर राहुल देव ने प्रभारी मंत्री श्री देवांगन को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ आमजनों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा बेहतर कार्ययोजना बनाकर लगातार प्रयास किया जा रहा है।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, पीएम उज्जवला योजना, जल जीवन मिशन, पीएम विश्वकर्मा योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि महत्वाकांक्षी योजनाओं सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, रोजगार, वन आदि विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा हुई और लक्ष्य के अनुरूप आवश्यक प्रगति लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी सत्यदेव शर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।

साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा 17 को

रायगढ़। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान नई दिल्ली की पहल पर 17 मार्च, 2024 दिन-रविवार को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक राष्ट्रव्यापी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मुल्यांकन परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। जिसमें ऐसे शिक्षार्थी जिनका पूर्व में पढना-लिखना अभियान अंतर्गत प्रमाणिकरण नहीं हुआ है, जो मोहल्ला साक्षरता केन्द्रों में पूर्व में पढ़ाई किये हैं, वे इस मूल्यांकन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। शिक्षार्थी सुविधानुसार उक्त समय के भीतर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। शिक्षार्थी को प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3 घण्टे का समय दिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा निति-2020 में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को प्रमुख रूप से फोकस किया गया है। जिले को शत-प्रतिशत साक्षर करने के उद्देश्य से केन्द्र प्रवर्तीत योजना उल्लास नव भारत साक्षरता का क्रियान्वयन जिला साक्षरता मिशन प्राधिकारण के अध्यक्ष एवं कलेक्टर के कुशल मार्ग दर्शन में प्रारंभ किया गया है।

शिक्षा मंत्री को मिले प्राइमरी स्कूल की बालिकाओं के मासूमियत से भरे पत्र

बच्चों ने लिखा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान से बालिकाओं के लिए है बहुत उम्मीद

रायपुर। प्रदेश भर के प्राइमरी स्कूल की छोटी-छोटी बालिकाओं के लिखे पत्र आज स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पास पहुंचे। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत इन सुंदर पत्रों को आज शिक्षा मंत्री ने देखा। हर पत्र अपने में मासूमियम से भरा बेटियों की अथाह प्रतिभा की दास्तां कह रहा था। इन पत्रों में छोटे बच्चों ने अपनी तुतलाहट भरी भाषा में चित्रों के माध्यम से एक बालिका भ्रुण की दास्तां कही।

एक बच्ची ने एक चित्र बनाया, इसमें एक बीज है जिसके भीतर भ्रुण है जिसकी हत्या की जा रही है। यह नहीं होता तो वो वृक्ष की असीम संभावना को छूता, उसी तरह बालिका भी अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करती।

मंत्री अग्रवाल इन पत्रों को पढ़कर और इनके मार्मिक चित्रों को देखकर भावुक हुए। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों ने मुझे पत्र के माध्यम से सुंदर संदेश भेजे हैं उन्हें मेरी ओर से धन्यवाद प्रेषित करना है। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि इन छोटी बालिकाओं के शब्दों का संसार सीमित है लेकिन इनकी संवेदना का संसार बहुत विस्तृत है। जिस तरह से इन्होंने एक बालिका भ्रुण की हत्या की भयावह दास्तां अपने चित्रों से व्यक्त की है वो इनकी गहरी भावनाओं को बताता है। इन प्रतिभाशाली बालिकाओं से छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्ज्वल लगता है।

शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने कहा कि लड़कियों के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षा से लड़कियां आत्मनिर्भर बनकर समाज में अपना योगदान देती हैं। शिक्षा लड़कियों को सशक्त बनाती है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने में मदद करती है। लड़कियों की शिक्षा समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब लड़कियां शिक्षित होती हैं, तो वे अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर निर्णय ले सकती हैं। वे अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकती हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। हमारी सरकार हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण के पक्षधर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में महिला आरक्षण बिल लाए हैं।

इसी क्रम में राज्य में महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन के अंतर्गत महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की राशि भी पहुंचने लगी है।

शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए पुलिस की भूमिका अहम - नीलेश क्षीरसागर

पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा उप पुलिस अधीक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

रायपुर। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा है कि राज्य की सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की है, साथ ही आदर्श आचार संहिता का पालन कराने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए विभिन्न निगरानी दलों के साथ भी पुलिस बल का समन्वय जरूरी है।

उन्होंने विधान सभा निर्वाचन 2023 के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर पुलिस बल की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय पर निगरानी रखने के लिए पुलिस का राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करना आवश्यक है। श्री क्षीरसागर ने कहा कि संवेदनशील मतदान केन्द्रों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल अन्य एजेंसियों की मदद से विशेष योजना तैयार कर कार्य करें। श्री क्षीरसागर न्यू सर्किट हाउस सभागार में लोकसभा निर्वाचन पूर्व पुलिस अधिकारियों के एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उदघाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले के निर्देशानुसार आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण में प्रदेश के 22 जिलों के पुलिस अधीक्षक, 11 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं 65 उप पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। इस अवसर पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी एस ध्रुव सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण के दौरान लोकसभा निर्वाचन के लिए राज्य पुलिस नोडल अधिकारी ओ पी पाल ने कहा है कि प्रदेश में शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की भूमिका अहम है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान राज्य पुलिस तथा जिला प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि बाहर से आने वाले अर्ध सैनिक बलों की टुकड़ियों को आवश्यक जरूरतों के लिए कोई असुविधा ना हो।

एक दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्र स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री यू एस अग्रवाल ने आदर्श आचरण संहिता, मीडिया मॉनिटरिंग एवं कंट्रोल सेंटर एवं शिकायत सेल के संबंध में जानकारी दी। वहीं मास्टर ट्रेनर अपूर्व प्रियेश टोप्पो ने निर्वाचन व्यय निगरानी , विनय अग्रवाल ने पोस्टल बैलेट, इलेक्ट्रानिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) और इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिक्रेट (ईडीसी) पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था एवं निर्वाचन संबंधी विभिन्न विषयों पर भी विशेषज्ञों ने जानकारियाँ साझा की।

समाज के लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए : सीएम यादव

एजेंसी। जिले के मानस भवन प्रांगण में आयोजित यादव समाज सम्मलेन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण के मानने वाले और राम और कृष्ण के लिए तो हमारी पूरी संस्कृति दुनिया में पहचानी जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन काल को हम देखें। समाज के सामने अपना उदाहरण बना के रखा और कोई नहीं हमारे गोपाल कृष्ण भगवान ही तो हैं जिनका पूरा जीवन सबके सामने है। कृष्ण की तरह हमें भी बनना चाहिए जिस तरह अपने कष्टों का समाधान किया, उसी तरह हमें भी अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। समाज के लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए और सब का साथ देना चाहिए। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल, राजनांदगांव सांसद संतोष पाण्डे, दुर्ग शहर विधायक गजेन्द्र यादव, रायपुर विधायक राजेश मूणत व यादव समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में समाज के सदस्य भी उपस्थित थे

छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधी परीक्षा समाप्त, परीक्षा पूर्व तैयारी से बच्चों को हुआ लाभ

दुर्ग दुर्ग जिले में 135 परीक्षा केन्द्रों में 30980 10वीं एवं 12वीं विद्यार्थियों का तनाव समाप्त हो गया है। क्योकि 10वीं की 3 पेपर व 12वीं के 04 पेपर समाप्त हो चुके है। इस सत्र में विद्यार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर देने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। क्योकि जिला शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न बैंक के माध्यम से प्रतिदिन प्रश्नों के सटीक उत्तर लिखने की तैयारी जनवरी और फरवरी माह में प्राचार्यो और शिक्षकों के माध्यम से प्रतिदिन करायी गयी।

खास खबर

स्वास्थ्य विभाग के बर्खास्त 05 हजार कर्मी हुये बहाल और 25 हजार कर्मियों को मिला रूका वेतन

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी 21 अगस्त 2023 से 12 सितम्बर 2023 तक हड़ताल में थे। इस अवधि का अवकाश व रूका वेतन स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर जारी कर दिया गया है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 30 हजार स्वास्थ्य कर्मियों को मिला हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल को आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के आंदोलन कर रहे कर्मचारियों का उस दौरान कार्यालय में अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्तगी व वेतन अस्वीकृत कर दिया गया था। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की थी। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने मुलाकात के बाद स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों को इन विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिये थे। निर्देश के परिपालन में बर्खास्त पांच हजार कर्मचारियों को वापस सेवा में ले लिया गया है। साथ ही 25 हजार कर्मचारियों का अंदोलन के दौरान रूका वेतन भी स्वीकृत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन ने स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का निज निवास कार्यालय में गत दिवस सौजन्य भेंट कर धन्यवाद दिया है। आंदोलन के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग के दो हजार कर्मचारियों के रूके हुये वेतन को देने का आदेश जारी नहीं किया गया हैं। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने इन कर्मियों का भी वेतन जारी करने का निवेदन स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल से किया हैं।

जिले के हाट-बाजारों और प्रमुख बसाहटों में एलईडी वैन एवं कला जत्था दल कर रहे योजनाओं का प्रचार-प्रसार

जगदलपुर। राज्य शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा एलईडी वैन तथा कला जत्था दलों के माध्यम से शासन की जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार हाट-बाजारों और प्रमुख बसाहटों में किया जा रहा है। इस दिशा में एलईडी वैन के माध्यम से योजनाओं पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा है,साथ ही कला जत्था दल द्वारा गीत,नाटक-प्रहसन के जरिए योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिसे ग्रामीणजन उत्सुकता के साथ देखकर लाभान्वित हो रहे हैं।

जनसम्पर्क विभाग द्वारा एलईडी वैन एवं कला जत्था दल के माध्यम से विगत दिवस धरमपुरा कॉलेज परिसर में आयोजित किसान सम्मेलन में योजनाओं से सम्बंधित लघु फिल्म प्रदर्शन किया गया। वहीं कला जत्था दल द्वारा योजनाओं पर केंद्रित प्रेरक प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही जगदलपुर विकासखण्ड के पुसपाल,बस्तर ब्लॉक के भैंसगांव एवं सुलेंगा,तोकापाल ब्लॉक के कुरेंगा एवं कलेपाल,दरभा विकासखंड के छिंदबहार,चिंगपाल साप्ताहिक बाजार सहित बकावंड विकासखण्ड के राजनगर एवं जुनवानी में एलईडी वैन एवं कला जत्था दल के माध्यम से महतारी वंदन योजना,कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इत्यादि का प्रचार-प्रसार किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को जनमन पत्रिका सहित विभिन्न जनहितकारी योजनाओं पर आधारित प्रचार साहित्य वितरित किया गया।

पीएम ई-बस सेवा योजना- छत्तीसगढ़ के चार शहरों को मिली 240 सिटी बसों की स्वीकृति

रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी

रायपुर। शहरों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को दुरुस्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम ई-बस सेवा योजना प्रारंभ की गई है। योजना के तहत राज्यों को शहरों की जनसंख्या के आधार पर बसों की संख्या निर्धारित की गई है। जिसके अनुसार रायपुर को 100, दुर्ग-भिलाई को 50, बिलासपुर को 50 तथा कोरबा को 40, इस प्रकार कुल 240 ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के चार प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की मंजूरी दी है। यह घोषणा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है, बल्कि पूरे देश के लिए एक मील का पत्थर भी है, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ और हरित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस मौके पर कहा कि राज्य में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत से शहरी परिवहन में क्रांति आएगी। यह पहल हमें पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को इस चैलेंज में सफल होने पर बधाई दी एवं भविष्य में और शहरों को भी इस योजना में शामिल करने के लिए प्रयास करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण हम नवाचार और स्थिरता की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। यह योजना हमारे नागरिकों के लिए एक उपहार है, जो न केवल पर्यावरण को बचाएगी, बल्कि हमारे जीवन को भी सुगम बनाएगी। ई-बसों का आगमन छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए एक नई और स्वच्छ परिवहन सेवा का द्वार खोलेगी। इन बसों के शुरू होने से पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी और शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की यह योजना राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय मदद को पारदर्शिता और उनके प्रदर्शन से जोड़ने की केंद्र की कोशिश का हिस्सा है। केंद्र सरकार की मंशा है कि यह योजना शहरों में मेट्रो के विकल्प या उसके सहयोगी साधन के रूप में विकसित हो ताकि लोगों को किफायती, भरोसेमंद और सुगम परिवहन की सुविधा मिले।

देश के समस्त राज्यों से राष्ट्रीय चैलेंज अंतर्गत प्राप्त शहरों के प्रतिस्पर्धात्मक के विश्लेषण उपरांत भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति तथा संचालन कमेटी (ष्टस्स्ष्ट) की छठवीं बैठक 01 मार्च को रायपुर तथा सातवीं बैठक 14 मार्च में छत्तीसगढ़ के 3 शहरों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

अपनी तरह की इस पहली योजना में केंद्र सरकार द्वारा शहरों को बसों की खरीद तथा उनके संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में बस डिपो जैसे इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी खर्च किया जाएगा। योजना की सामान्य शर्तों में यह भी शामिल है कि प्रोजेक्ट के तहत दिए जाने वाले पैसे का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा, ताकि पूरी पारदर्शिता रहे। शहरों को हर तीन महीने में बसों के संचालन का हिसाब-किताब देना होगा। योजना के तहत तीन तरह की बसें स्टैंडर्ड, मीडियम और मिनी चलाई जाएंगी। शहरों को जनसंख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा गया है। बीस से चालीस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 150, दस से बीस लाख तथा पांच से दस लाख तक की आबादी वाले शहरों को 100-100 तथा पांच लाख से कम आबादी वाले शहरों को 50 ई-बसों की पात्रता थी जिसके आधार पर रायपुर को 100 मीडियम ई-बस, दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बस, बिलासपुर को 35 मीडियम तथा 15 मिनी ई-बस और कोरबा को 20 मीडियम तथा 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बसों का क्रय तथा संचालन एजेंसी का चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित किलोमीटर संचालन के लिहाज से दी जाएगी और अगर बसें इससे कम किलोमीटर चलती हैं तो केंद्रीय सहायता उसी के अनुपात में कम हो जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा शहरों के प्रदर्शन के आधार पर पैसा दिया जाएगा। ई-बस सेवा से छत्तीसगढ़ के शहरों में कम कार्बन उत्सर्जन से वायु गुणवत्ता में सुधार तथा पर्यावरणीय संरक्षण के साथ-साथ कम ऊर्जा खपत और बेहतर ईंधन दक्षता एवं आरामदायक सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

खाद्य मंत्री बघेल ने 1 करोड़ 78 लाख के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

रायपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड के नगर पंचायत मारो में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने 1 करोड़ 78 लाख 14 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया । विकास कार्यों के भूमि पूजन में विभिन्न वार्डों में आर सी सी नाली, सी सी रोड, एवं मंगल भवन शामिल है। खाद्य मंत्री ने हितग्राहियों नये राशन कार्ड का भी वितरण किया।

खाद्य मंत्री बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत 24.72 लाख किसानों के खाते में 13,320 करोड़ रूपए की अदान सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का नया रिकार्ड प्रदेश में बना है। 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों से 145 लाख मीट्रिक टन की धान खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को 31 हजार 914 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी 5 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान वितरण शुरू हो गया है। राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभान्वित हो रहे है। प्रदेश की महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 36 लाख 76 हजार गैस कनेक्शन का लाभ मिला है। इस अवसर पर टार्जन साहू, अंजू बघेल, परस वर्मा, धनलाल देशलहरे, मती आराध्या माधो छत्रिय, एवं समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

तिल्दा नेवरा में 5.24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

विकास कार्यों से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगेः मंत्री बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल आज तिल्दा-नेवरा में आयोजित लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने यहां 5.24 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। श्री अग्रवाल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ससाहोली का नाम जैन मुनि श्री विद्या सागर जी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की साथ ही तिल्दा नेवरा में बीएड कॉलेज खोले जाने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद प्रियदर्शिनी स्कूल और शासकीय विद्यालय भीमोरी में निर्माण कार्य के लिए 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की।

मंत्री श्री अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद विकास के कार्यों में तेजी आई है। डबल इंजन सरकार की वजह से बेहतर समन्वयन के कारण योजनाओं को क्रियान्वित करने में आसानी हो रही है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और विकास कार्यों से रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। श्री अग्रवाल ने यहां 157 लाख रुपए से निर्मित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में 50 सीटर बालक छात्रावास, 247 लाख रुपए की लागत से बने 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र, 42 लाख रुपए से निर्मित उप पंजीयक कार्यालय भवन और 27 लाख से बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हमर क्लिनिक का लोकार्पण किया। साथ ही बी.एन.बी. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल सासाहोली और स्वामी आत्मानंद कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 18-18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले प्रार्थना शेड का शिलान्यास किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने की और सांसद सुनील सोनी विशिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर लेमिक्षा गुरू डहरिया, अनिल अग्रवाल, ईश्वर यदु, देवादास टंडन, विभागीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित थे।

पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोडमेप पर हुई चर्चा

पर्यावरण को सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी : ओपी चौधरी

लोकशक्ति। संवाददाता।

रायपुर। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास की परिकल्पना को सार्थक करने के लिये 'छत्तीसगढ़ विजन 2047' पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत ने की।

पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास हेतु अगले 25 वर्षों के रोडमेप पर चर्चा करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी को बदलते हुए वक्त को समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के लिए खुद को भी बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार सतत विकास के लिए अपने बजट में 2047 में छत्तीसगढ़ को भी विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में देखना चाहती है और इसके लिए लॉन्ग टर्म गोल के रूप में ही अमृतकाल विजन डॉक्यूमेंट ञ्च 2047 की तैयारी की जा रही है जिसे छत्तीसगढ़ की स्थापना के दिन 1 नवंबर को लांच किया जाएगा।

मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास का होना अनिवार्य है और इस सेक्टर में काफी ग्रोथ भी हो रही है। इसके साथ ही हमें सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाने की आवश्यकता है और अगले पांच साल में इसे बढ़ाने के लिए काम करना है। इसकी शुरआत भी कर दी गयी है और अगले तीन साल के भीतर नवा रायपुर इनोवेशन तथा आईटी हब के रूप के जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी शुरू होगी।

आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें ये जानकारी हैरानी होगी कि बड़े शहरों में उद्योगों से ज्यादा प्रदूषण सड़क पर चल रही वाहनों के जरिए होता है और इस पर नियंत्रण पाना बेहद जरुरी है। इसके लिए हम सभी को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है और ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण को संरक्षण करने में अपनी महती भूमिका निभाए।

छत्तीसगढ़ - विजन 2047 पर आयोजित इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के सचिव तथा छत्तीसगढ़ सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने कहा कि हमें ये सोचना होगा कि हमने अभी से तैयारी शुरू नहीं की तो साल 2047 तक भविष्य कैसा होगा। उन्होंने कहा कि जैसे प्रत्येक जीवित इंसान की सेहत उसके लिए जरूरी है वैसे ही पेड़ पौधों की अच्छी सेहत हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, उनके भीतर भी जीवन है और उनके जीवन से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। श्री भगत ने कहा कि आज तकनीक का दौर है और इसमें तेजी से बदलाव आ रहा है, लेकिन हमें इस बदलाव में भी पर्यावरण का ध्यान रखना होगा ताकि हम खुद और हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सुरक्षित रह सकें।

जंजीरों में बंधा कुत्ता मालिकों का खिलौना लेकिन दूसरों के लिये बना आदमखोर

कुछ लोग आज कल ज्यादा कमाई होने पर कुत्ते पालने लग जाते हैं परंतु ये भूल जाते हैं कि कुत्ता हिंसात्मक भी होता है और आदमखोर भी बनने में एक सेकेंण्ड का वक्त लगता है । देखिये कोई भी जानवर पालना एक अच्छी बात होती है परंतु दूसरों के हितों और सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी होता है ।

संवाददाता।

भारत के विभिन्न राज्यों में रह रहे लोगों को कुत्तों से प्रेम है। यही वजह है कि लोग इन्हें अपने घरों में देते हैं और अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करते हैं। हालांकि, समय-समय पर हमारे सामने कुत्तों द्वारा इंसानों पर होने वाले हमले की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं।

कुत्तों के साथ कई चौंकाने वाली घटनाएं होती रहती हैं। एक खबर के अनुसार : ऐसी ही घटना अब हरियाणा के सोनीपत में हुई है. एक महिला अपने पिटबुल डगलस को लिफ्ट में लेकर चल रही है। इसी बीच एक व्यक्ति भी आ गया. तभी पिटबुल ने उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. पीड़िता ने पुलिस की भूमिका निभाई है.

तदनुसार, यह घटना हाई नेशनल कुंडली पार्क रेजीडेंसी की है। सुदर्शन नाम का एक व्यक्ति हमेशा सुबह की सैर पर रहता था। जब शख्स लिफ्ट के पास लौटा. इसी दौरान लिफ्ट में नवा की पत्नी पूनम भी अपने पिटबुल कुत्ते के साथ थीं। जैसे ही लीचा दरवाजा खोलती है और लिफ्ट में मौजूद व्यक्ति पिटबुल के साथ खुलता है। पिटबुल ने शख्स के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया. जिसके बाद वह गंभीर हो गये. ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. अब उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. सुदर्शन के मुताबिक, सोसायटी में ऐसे एक नहीं बल्कि चार कुत्ते हैं। प्रतिबंध लगा दिया है। लोग आज भी बुल डॉग को पीटते हैं. सुदर्शन ने कहा कि मैंने पुलिस में विपरीत भूमिका निभाई है. लेकिन पुलिस अधिकारी सख्ती नहीं बरत रहे हैं. रेजीडेंसी वेलफेयर एसोसिएशन से भी शिकायत की गई है। यह देखते हुए कि उन्होंने दिया, कुत्ते को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

लेकिन सवाल ये है कि प्रतिबंध के बावजूद लोग इस नस्ल के कुत्ते को सुरक्षित रूप से पाल रहे हैं।

स्वामी,मुद्रक,प्रकाशक प्रेमेन्द्र अग्रवाल द्वारा अस्मा पब्लिशर्स इण्डिया प्राईवेट लि.,जयस्तंभ चौक, रायपुर से मुद्रित कर तथा 5/756 रामसागरपारा, सिंधी स्कूल के पीछे, स्टेशनरी हाऊस, रायपुर 492001 (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक प्रेमेन्द्र अग्रवाल ।
www.lokshakti.in, lokshaktidaily@gmail.com, twitter.com/lokshaktidaily, facebook.com/lokshaktidaily कार्यकारी संपादक : राजेश अग्रवाल (किसी भी विवाद पर न्यायालय क्षेत्र रायपुर होगा)